आर्थिक समीक्षा

सत्यमेव जयते
Government of India

2023-24

आर्थिक समीक्षा

2023-24

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली–110001
जुलाई, 2024

विषय सूची

	vii	*प्रस्तावना*
	xiii	*आभारोक्ति*
	xv	*संकेताक्षर*
	xxxiii	*तालिकाओं की सूची*
	xxxv	*चार्टों की सूची*
	xliii	*बॉक्स की सूची*
अध्याय सं.	**पृष्ठ सं.**	**अध्याय का नाम**
1		**अर्थव्यवस्था की स्थिति: निरंतर आगे बढ़ते हुए**
	1	वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
	8	एक लचीली घरेलू अर्थव्यवस्था
	15	वृहद आर्थिक स्थिरता विकास सुरक्षा
	29	समावेशी विकास
	31	परिप्रेक्ष्य
2		**मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: स्थिरता ही मूलमंत्र**
	33	परिचय
	34	मौद्रिक विकास
	38	वित्तीय मध्यस्थता
	38	बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन और ऋण उपलब्धता
	56	भारतीय पूंजी बाजार में रुझान
	66	बीमा क्षेत्र में विकास
	69	पेंशन क्षेत्र में विकास
	74	मूल्यांकन और दृष्टिकोण
3		**कीमतें और मुद्रास्फीति - नियंत्रण में**
	75	परिचय
	77	घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति
	79	महामारी के बाद की दुनिया में कोर मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव
	83	खाद्य मुद्रास्फीति
	87	खुदरा मुद्रास्फीति में अंतरराज्यीय अंतर
	88	दृष्टिकोण और समाधान
	91	अनुलग्नक 1
4		**बाह्य क्षेत्र: समृद्धि के बीच स्थिरता**
	93	प्रस्तावना
	94	वैश्विक व्यापार की गतिशीलता में बदलाव
	96	भारत का व्यापार: वैश्विक उथल-पुथल के बीच लचीलापन
	120	अनुकूल चालू खाता शेष
	125	पूंजीगत खाता शेष
	136	अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति

137 स्थिर विदेशी ऋण की स्थिति
138 संभावनाएं और चुनौतियां

5 **मध्यम अवधि परिदृश्य : नए भारत के लिए विकास दृष्टि**
141 सन्दर्भ निर्धारित करना
144 अल्प से मध्यम अवधि में नीतिगत फोकस के प्रमुख क्षेत्र
151 अमृत काल के लिए विकास रणनीति
162 मध्यम अवधि में संभावना

6 **जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण: समझौताकारी सामंजस्य**
165 परिचय
169 भारत की जलवायु कार्रवाई की वर्तमान स्थिति
170 भारत के लिए अनुकूलन महत्वपूर्ण है
173 निम्न कार्बन विकास और ऊर्जा संरचना
186 कार्बन की कीमत तय करने के लिए बाजार : भारतीय कार्बन बाजार
189 जलवायु वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ : घटनाक्रम
191 जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के समाधान के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय पहल
193 निष्कर्ष

7 **सामाजिक क्षेत्र: कल्याण जो सशक्त करे**
195 परिचय
197 विकास को सशक्त कल्याण के साथ जोड़ना
232 महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण
239 ग्रामीण अर्थव्यवस्था: विकास इंजन को गति देना
249 ग्रामीण शासन: जमीनी स्तर पर डिजिटल परिवर्तन की कहानी
253 निष्कर्ष और आगे का मार्ग

8 **रोजगार और कौशल विकास: गुणवत्ता की ओर**
255 परिचय
256 वर्तमान रोजगार परिदृश्य
259 युवा और महिला रोजगार
272 भारत में नौकरियों का विकसित परिदृश्य
279 2036 तक रोजगार सृजन की आवश्यकता
290 कौशल निर्माण में विकास और प्रगति
297 निष्कर्ष और आगे की राह

9 **कृषि और खाद्य प्रबंधन : यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोत्तरी अवश्य है**
299 परिचय
301 कृषि उत्पादन: प्रदर्शन और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
315 संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक हैं
318 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (एफपीआई): प्रसंस्करण क्षमता
320 खाद्य प्रबंधन: खाद्य सुरक्षा के लिए सामाजिक जाल
321 निष्कर्ष

10 **उद्योग: मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य**

323 परिचय

326 प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन और संबंधित मुद्दे

338 क्रॉस-कटिंग थीम

347 निष्कर्ष एवं दृष्टिकोण

11 **सेवाएँ: विकास के अवसरों को बढ़ावा देना**

349 परिचय

350 सेवा क्षेत्र के निष्पादन का अवलोकन

355 सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वित्तपोषण स्रोत

356 प्रमुख सेवाएँ: क्षेत्रवार निष्पादन

375 चुनौतियाँ और अवसर

376 निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

12 **अवसंरचना: संभावित विकास को प्रोत्साहन**

379 परिचय

380 अवसंरचना वित्तपोषण: सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देना

384 अवसंरचना क्षेत्रों में विकास

414 चुनौतियाँ और अवसर

416 सुविधा प्रदान करना और बाधाओं को दूर करना

419 निष्कर्ष और दृष्टिकोण

13 **जलवायु परिवर्तन और भारत: हमें इस समस्या को अपने नजरिए से क्यों देखना चाहिए**

421 परिचय

423 वर्तमान दृष्टिकोण दोषपूर्ण क्यों है?

433 पश्चिमी पद्धतियों को अपनाने से विकासशील दुनिया पर नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा

439 भारतीय पद्धति: एक संधारणीय जीवनशैली

445 निष्कर्ष

प्रस्तावना: समझौतों और आम सहमति के माध्यम से देश का संचालन

अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी है

अप्रैल में हमने नया वित्त वर्ष शुरू किया। मई में हमें पता चला कि वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान है। जून में नई सरकार ने कार्यभार संभाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में लौटी है। उनका अभूतपूर्व तीसरा लोकप्रिय जनादेश राजनीतिक और नीतिगत निरंतरता का संकेत देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर स्थिति में है, जो भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन प्रदर्शित करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने नीति निर्माताओं - राजकोषीय और मौद्रिक - दोनों के साथ आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ कोविड के बाद की रिकवरी को मजबूत किया है। फिर भी, उच्च विकास आकांक्षाओं वाले देश के लिए परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। सुधार को कायम रखने के लिए घरेलू मोर्चे पर कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि व्यापार, निवेश और जलवायु जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाना असाधारण रूप से कठिन हो गया है।

वित्त वर्ष 24 में उच्च आर्थिक वृद्धि पिछले दो वित्तीय वर्षों में क्रमश: 9.7% और 7.0% की वृद्धि दर के बाद आई है। मुख्य मुद्रास्फीति दर काफी हद तक नियंत्रण में है, हालांकि कुछ विशिष्ट खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर बढ़ी हुई है। वित्त वर्ष 24 में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 23 की तुलना में कम था, तथा वर्ष के लिए चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% है। वस्तुत:, चालू खाते में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अधिशेष दर्ज किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है। सार्वजनिक निवेश ने पिछले कई वर्षों में पूंजी निर्माण को बनाए रखा है, जबकि निजी क्षेत्र ने अपनी बैलेंस शीट की गिरावट को दूर किया है और वित्त वर्ष 22 में निवेश करना शुरू कर दिया है। अब, इसे सार्वजनिक क्षेत्र से कमान लेनी होगी और अर्थव्यवस्था में निवेश की गति को बनाए रखना होगा। संकेत उत्साहवर्धक हैं।

राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से पता चलता है कि गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण, जिसे वर्तमान मूल्यों में मापा जाता है, में वित्त वर्ष 21 में गिरावट के बाद वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में जोरदार वृद्धि हुई। तथापि, विशेष रूप से, मशीनरी और उपकरणों में निवेश में लगातार दो वर्षों, वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 में गिरावट आई, तथा उसके बाद इसमें जोरदार उछाल आया। वित्त वर्ष 24 के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण का विस्तार जारी रहा, लेकिन धीमी दर से।

विदेशी निवेशकों की रुचि बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता होगी

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्लेषण का बड़ा विषय है, किंतु रुका हुआ है। भारत के भुगतान संतुलन पर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि नई पूंजी के डॉलर अंतर्वाह के संदर्भ में मापी गई बाहरी निवेशकों की निवेश रुचि वित्त वर्ष 2024 में 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 47.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यह मामूली गिरावट वैश्विक रुझान के अनुरूप है। आय का पुनर्निवेश वही रहा है । वित्त वर्ष 23 में विदेशी निवेश का प्रत्यावर्तन 29.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 24 में 44ण्5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कई निजी इक्विटी निवेशकों ने भारत में तेजी से बढ़ते इक्विटी बाजारों का लाभ उठाया और लाभ कमाते हुए बाहर निकल गए। यह एक स्वस्थ बाजार परिवेश का संकेत है जो निवेशकों को लाभदायक निकास प्रदान करता है, जिससे आने वाले वर्षों में नए निवेश आएंगे। जैसा कि कहा गया है, आने वाले वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए माहौल कई कारणों से बहुत अनुकूल नहीं है।

विकसित देशों में ब्याज दरें कोविड के वर्षों के दौरान और उससे पहले की तुलना में बहुत अधिक हैं। इसका अर्थ न केवल वित्तपोषण की उच्च लागत है, बल्कि विदेश में निवेश करने के अवसर की लागत भी अधिक होती है। दूसरा, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सक्रिय औद्योगिक नीतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिसमें घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने वाली पर्याप्त सब्सिडी शामिल होगी। तीसरा, पिछले दशक में की गई प्रभावशाली प्रगति के होने के बावजूद, अंतरण मूल्य निर्धारण, करों, आयात शुल्कों और गैर-कर नीतियों से संबंधित अनिश्चितताओं और व्याख्याओं का समाधान किया जाना अभी भी बाकी है। अंत में, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, जो बढ़ रही हैं, भारत में निवेश को प्राथमिकता देने के अन्य कारणों के बावजूद, पूंजी प्रवाह पर अधिक प्रभाव डालेंगी।

रोजगार पर संरचनात्मक ताकतों का नहीं बल्कि झटकों का असर पड़ा है

रोजगार सृजन के संबंध में, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शहरी रोजगार संकेतकों पर त्रैमासिक और ग्रामीण भारत सहित पूरे देश के लिए वार्षिक आंकड़े उपलब्ध कराता है। कृषि रोजगार में वृद्धि ग्रामीण भारत में रिवर्स माइग्रेशन (महानगरों और शहरों से गाँव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है) और श्रम बल में महिलाओं के प्रवेश द्वारा आंशिक रूप से समझाई गई है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में लगभग 2ण्0 लाख भारतीय कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के आंकड़े उपलब्ध हैं। 2013-14 और 2021-22 के बीच फैक्ट्री

नौकरियों की कुल संख्या में सालाना 3.6% की वृद्धि हुई। कुछ अधिक संतोषजनक बात यह रही कि छोटी फैक्टरियों (सौ से कम श्रमिकों को रोजगार देने वाली फैक्टरी) की तुलना में बड़ी फैक्टरियों (सौ से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली फैक्टरी) में रोजगार में 4.0% की तेजी से वृद्धि हुई। छोटे कारखानों में वार्षिक वृद्धि दर 1.2% थी। इस अवधि में भारतीय कारखानों में रोजगार की कुल संख्या 1.04 करोड़ से बढ़कर 1.36 करोड़ हो गई है। भारत में अभी तक सेवाओं से संबंधित कोई वार्षिक सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों - कृषि, विनिर्माण और सेवाओं सहित उद्योग - में वार्षिक अंतराल पर भी सृजित (औपचारिक और अनौपचारिक) नौकरियों की पूर्ण संख्या पर समय पर आंकड़ों की उपलब्धता का अभाव, उच्च आवृत्तियों की तो बात ही छोड़िए, देश में श्रम बाजार की स्थिति के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण को रोकता है।

2022-23 के लिए असमाविष्ट उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की तुलना जब 'भारत में असमाविष्ट गैर-कृषि उद्यमों (सन्निर्माण को छोड़कर) के प्रमुख संकेतकों' के एनएसएस 73वें दौर के परिणामों से की जाती है, तो पता चलता है कि इन उद्यमों में कुल रोजगार 2015-16 में 11ण्1 करोड़ से घटकर 10.96 करोड़ हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में 54 लाख श्रमिकों की कमी आई, लेकिन व्यापार और सेवाओं में कार्यबल के विस्तार से नौकरियों में वृद्धि हुई, जिससे इन दो अवधियों के बीच असमाविष्ट उद्यमों में श्रमिकों की संख्या में कुल कमी लगभग 16.45 लाख तक सीमित हो गई। यह तुलना विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों में आये बड़े उछाल को छुपाती है जो 2021-22(अप्रैल 2021- मार्च 2022) और 2022-23 (अक्तूबर 2022-सितम्बर 2023) के बीच हुई प्रतीत होती है।

भारत को शीघ्रता से दो बड़े आर्थिक झटके लगे हैं। बैंकिंग प्रणाली में अशोध्य ऋण और उच्च कॉर्पोरेट ऋणग्रस्तता इनमें से एक थे। इसे नियंत्रण में लाने में वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल से अधिक का समय लग गया। कोविड महामारी दूसरा झटका था और पहले झटके के तुरंत बाद ऐसा घटित हुआ। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार सृजन की क्षमता संरचनात्मक रूप से कमजोर है। फिर भी, आगे बढ़ते हुए, यह कार्य कठिन है।

जनवरी 2023 में प्रकाशित पिछले आर्थिक सर्वेक्षण और इस सर्वेक्षण के बीच भू-राजनीतिक परिवेश में बड़े बदलाव हो रहे हैं। 2047 में विकसित भारत की ओर भारत के कदम बढ़ाने की वैश्विक पृष्ठभूमि, 1980 से 2015 के बीच चीन के उदय के दौरान की पृष्ठभूमि से अधिक भिन्न नहीं हो सकती। तब, वैश्वीकरण अपने लम्बे विस्तार के शिखर पर था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भू-राजनीति काफी हद तक शांत हो गई थी, तथा पश्चिमी शक्तियों ने चीन के उदय और विश्व अर्थव्यवस्था में उसके एकीकरण का स्वागत किया तथा उसे प्रोत्साहित भी किया। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंताएं तब इतनी व्यापक या गंभीर नहीं थीं जितनी कि अब हैं। चौथा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से सभी कौशल स्तरों - निम्न, अर्ध और उच्च - के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की एक बड़ी छाया उत्पन्न हो गई है। ये आने वाले वर्षों और दशकों में भारत के लिए सतत उच्च विकास दर के मार्ग में बाधाएं और रुकावटें पैदा करेंगे। इन पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के बीच एक महागठबंधन की आवश्यकता है।

रोजगार सृजन निजी क्षेत्र के लिए वास्तविक लक्ष्य है

यह बात दोहराना उचित होगा कि रोजगार सृजन मुख्यत: निजी क्षेत्र में होता है। दूसरा, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कई (सभी नहीं) मुद्दे तथा उनमें की जाने वाली कार्रवाई राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, भारतीयों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने तथा 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पूरी करने के लिए भारत को त्रिपक्षीय समझौते की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।

एक से अधिक मामलों में, कार्रवाई निजी क्षेत्र के हाथ में है। वित्तीय कार्य-निष्पादन के संदर्भ में कॉर्पोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन इतना अच्छा कभी नहीं रहा। 33,000 से अधिक कंपनियों के नमूने के परिणाम बताते हैं कि वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 23 के बीच के तीन वर्षों में भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का कर-पूर्व लाभ लगभग चार गुना हो गया। इसके अलावा, अखबारों की सुर्खियों ने हमें बताया कि कॉर्पोरेट मुनाफे और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वित्त वर्ष 24 में 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बिजनेसलाइन ने बताया, "निफ्टी-500 यूनिवर्स के लिए कॉर्पोरेट लाभ पिछले वित्त वर्ष में 30 प्रतिशत बढ़कर ₹14.11 लाख करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 23 में ₹10.88 लाख करोड़ था। नोमिनल जीडीपी साल-दर-साल 9ण्6 प्रतिशत बढ़कर ₹295 लाख करोड़ (₹269 लाख करोड़ से)[1]'' हो गई। नियुक्ति और मुआवजे में वृद्धि शायद ही इसके साथ हो। लेकिन, काम पर रखना और श्रमिक मुआवजे में वृद्धि करना कंपनियों के हित में है।

केंद्र सरकार ने पूंजी निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए सितंबर 2019 में करों में कटौती की। क्या कॉर्पोरेट क्षेत्र ने इस पर प्रतिक्रिया दी है? वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच, निजी क्षेत्र के गैर-वित्तीय सकल स्थिर पूंजी निर्माण (**GFCF**) में संचयी वृद्धि मौजूदा कीमतों में 52% है। इसी अवधि के दौरान, सामान्य सरकार (जिसमें राज्य भी शामिल हैं) में संचयी वृद्धि 64% है। यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं लगता।

1. 'निवेश लागत में कमी के कारण कॉर्पोरेट लाभ जीडीपी के मुकाबले 15 साल के उच्चतम स्तर पर', बिजनेसलाइन, 11 जून 2024 (https://www.thehindubusinessline.com/economy/corporate.profit.to.gdp.hits.15.year.high.as.input.cost.moderates/article68277319.ece)

हालाँकि, जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। मशीनरी एवं उपकरण तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में निजी क्षेत्र के जीएफसीएफ में वित्त वर्ष 23 तक के चार वर्षों में संचयी रूप से केवल 35% की वृद्धि हुई है। इस बीच, 'आवास, अन्य भवन और संरचनाओं' में इसके जीएफसीएफ में 105% की वृद्धि हुई है। यह कोई अच्छा मिश्रण नहीं है। दूसरा, मीडिया एवं मनोरंजन तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में निवेश की धीमी गति से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत के प्रयास में देरी होगी, भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार में देरी होगी, तथा उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक नौकरियों की संख्या में कमी आएगी।

फिर भी, आंकड़ों में एक सकारात्मक बात भी है। वित्त वर्ष 21 के बाद से दो वर्षों में निजी क्षेत्र द्वारा जीएफसीएफ में तेजी से वृद्धि हुई है। सामान्य सरकार जीएफसीएफ में वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 23 के बीच संचयी रूप से 42% की वृद्धि हुई। गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र के समग्र जीएफसीएफ में 51% की वृद्धि हुई; मशीनरी एवं उपकरण तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में निवेश में 38% की वृद्धि हुई। इसलिए, निजी क्षेत्र के जीएफसीएफ के इन दो महत्वपूर्ण उप-घटकों में वृद्धि सामान्य सरकार के समग्र जीएफसीएफ के समान है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर गौर करना जरूरी है। उन्हें निवेश जारी रखना चाहिए। ऐसा करने के लिए उन्हें मांग की स्पष्टता की आवश्यकता है। यह रोजगार और आय वृद्धि से आता है।

हाल ही में प्रकाशित एक लेख[2] में, द इकोनोमिस्ट में स्वतंत्र शोध का हवाला दिया है, जिसमें अगले दशक में भारत के सेवा निर्यात में धीमी गिरावट की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि दूरसंचार में तेजी और इंटरनेट के उदय ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन प्रौद्योगिकी विकास की अगली लहर इसमें रुकावट डाल सकती है। इस परिवेश में, कॉर्पोरेट क्षेत्र की जिम्मेदारी जितनी स्वयं के प्रति है उतनी समाज के प्रति भी है, कि वह इस बारे में अधिक गंभीरता से सोचे कि किस प्रकार 'एआई' श्रमिकों को विस्थापित करने के बजाय श्रम को बढ़ाएगा। पिछले दो वर्षों में आईटी क्षेत्र में भर्ती की गति काफी धीमी हो गई है। हमारे पास देश में नियमित आधार पर समग्र कॉर्पोरेट नियुक्ति की पूरी जानकारी नहीं होती है। किसी भी मामले में, पूंजी-प्रधान और ऊर्जा-प्रधान एआई को लागू करना संभवत: उन अंतिम मदों में से एक है, जिसकी बढ़ती हुई निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था को आवश्यकता है।

जून 2024[3] में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक स्टाफ चर्चा नोट में कहा गया है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बड़े पैमाने पर श्रम व्यवधानों और असमानता के बारे में गहरी चिंताएं जताई हैं। आईएमएफ एसडीएन ने देशों के बीच स्वचालित सूचना विनिमय के बेहतर प्रवर्तन और पूंजीगत लाभ पर संवर्धित कराधान के माध्यम से पूंजी पर अच्छी तरह से डिजाइन किए गए अतिरिक्त कॉर्पोरेट लाभ करों और उच्च व्यक्तिगत आय करों की सिफारिश की है। हालाँकि, रोजगार का संबंध सिर्फ उससे मिलने वाली आय से नहीं है, बल्कि इसका संबंध गरिमा, आत्म-मूल्य, आत्म-सम्मान, स्वाभिमान तथा परिवार और समुदाय में प्रतिष्ठा से है। यही कारण है कि अत्यधिक लाभ कमाने में लगे भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए यह उचित है कि वह रोजगार सृजन की अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से ले। बेशक, इसके लिए सही दृष्टिकोण और कौशल वाले लोगों को ढूंढना होगा।

इसके लिए एक और त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है - सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच। इस समझौते का उद्देश्य भारतीयों को तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाने और उससे आगे निकलने के लिए कौशल और सुसज्जित करने के मिशन को पुनर्जीवित करना है। इस मिशन में सफल होने के लिए, सरकारों को उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों को इस विशाल कार्य में अपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए स्वतंत्र करना होगा। उदाहरण के लिए, वर्षों से कई संशोधनों के बावजूद, देश में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षुता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम अभी भी प्रगति पर है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की उच्च शिक्षा को नियामक निगरानी से मुक्त कर बाजार निगरानी की ओर ले जाने का प्रस्ताव करती है। एक कॉर्पोरेट क्षेत्र जो पाठ्यक्रम, मूल्यांकन मानकों और संकाय के लिए उपयोगी जानकारी के साथ उच्च शिक्षा के डिजाइन को आकार देने में मदद करता है, वह उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो बाजार की प्रतिस्पर्धा लाएगा और नियामक निगरानी का स्थान लेगा। द इकोनॉमिस्ट के एक अन्य लेख[4] में चीन के विज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनने की सराहना की गई है, जो कि कॉर्पोरेट क्षेत्र और शिक्षा जगत के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एकजुट होकर कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा होनी चाहिए।

वास्तविक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

कॉर्पोरेट क्षेत्र की भूमिका आज से पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व के दो अन्य क्षेत्रों का यहां उल्लेख करना उचित होगा। महामारी के दौरान भारतीय खुदरा निवेशक बाजार स्थिरता के आधार के रूप में उभरे हैं। दीर्घावधि के लिए निवेश की प्रवृत्ति

2. 'क्या सेवाएँ दुनिया को समृद्ध बनाएंगी?', द इकोनॉमिस्ट, 24 जून 2024 (https://www.economist.com/finance.and.economics/2024/06/24/will.services.make.the.world.rich)

3. 'जनरेटिव एआई से लाभ का विस्तार: राजकोषीय नीतियों की भूमिका', स्टाफ चर्चा नोट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जून 2024 (https://tinyurl.com/39dy7dv3)

4. 'चीन एक वैज्ञानिक महाशक्ति बन गया है', द इकोनॉमिस्ट, 12 जून 2024 (https://www.economist.com/science.and.technology/2024/06/12/china.has.become.a.scientific.superpower)

को पोषित और कायम रखना होगा। विकसित देशों में वित्तीय नवाचारों के नाम पर छिपे तौर पर लीवरेज दांव से प्रेरित बाजार प्रथाओं का, कम प्रति व्यक्ति आय वाले विकासशील देश में कोई स्थान नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ रहा है, उसी प्रकार भारतीय बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह अच्छी बात है। लाभ कमाने वाले बैंक ज़्यादा उधार देते हैं। अच्छे समय को बनाए रखने के लिए, पिछले वित्तीय चक्र की मंदी के सबक को न भूलना जरूरी है। बैंकिंग उद्योग को दो एनपीए चक्रों के बीच के अंतराल को बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसे ग्राहकों की कीमत पर अल्पकालिक लाभ कमाने के प्रलोभन का भी विरोध करना चाहिए। उत्पाद की गलत बिक्री इतनी व्यापक है कि इसे कुछ अति उत्साही विक्रय कर्मियों की गलती मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। यही बात बीमा उद्योग के बारे में भी कही जा सकती है। बीमा दावों का शीघ्र और उचित निपटान तथा अस्वीकृति दर में कमी बीमा पैठ बढ़ाने के लिए आवश्यक है। गलत बिक्री और गलत बयानी की स्वीकृति और परिणामी नुकसान की भरपाई करना एक अच्छा व्यवसाय अभ्यास है, जो स्टॉकब्रोकिंग, फंड प्रबंधन, बैंकिंग और बीमा फर्मों के लिए अनिवार्य है।

रोजगार और आय वृद्धि से उत्पन्न उच्च मांग से कॉर्पोरेट को लाभ होता है। घरेलू बचत को निवेश उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से वित्तीय क्षेत्र को लाभ होता है। आने वाले दशकों में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परिवर्तन निवेश को पूरा करने के लिए इन संबंधों को और मजबूत और लंबे समय तक चलना चाहिए। अल्पकालिकता इन संबंधों को कमजोर कर सकती है।

भारत की कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, बैठे रहने की आदतें और अस्वास्थ्यकर भोजन एक घातक मिश्रण है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को कमजोर कर सकता है और भारत की आर्थिक क्षमता को कम कर सकता है। आदतों के इस जहरीले मिश्रण में निजी क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा है, और यह निकट दृष्टिक है। भारतीयों की उभरती हुई खाद्य उपभोग की आदतें न केवल अस्वास्थ्यकर हैं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी असंतुलित हैं। भारत की पारंपरिक जीवनशैली, भोजन और व्यंजनों ने सदियों से यह दिखाया है कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए स्वस्थ तरीके से कैसे रहा जाए। भारतीय व्यवसायों के लिए इनके बारे में जानना और इन्हें अपनाना व्यावसायिक दृष्टि से उचित है, क्योंकि उनके पास एक वैश्विक बाजार है, जिसका नेतृत्व करने की आवश्यकता है, न कि इसका दोहन करने की।

सरकारें अपनी ओर सेण्ण्ण्ण

नीति निर्माताओं को – चाहे वे निर्वाचित हों या नियुक्त को भी चुनौतियों का सामना करना होगा। मंत्रालयों, राज्यों तथा संघ और राज्यों के बीच बातचीत, सहयोग, सहभागिता और समन्वय होना चाहिए। सरकार के बाहर बहुत कम लोग भारत जैसे (जनसंख्या) आकार, (भौगोलिक) विस्तार तथा सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले राष्ट्र को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर संचालित करने और बदलने की जटिलता को समझ सकते हैं। जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और सिविल सेवा के साथ-साथ जिलों, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ अपने संपर्क के कारण, राजनीतिक वर्ग के पास इस जटिलता को (कम से कम) आंशिक रूप से समझने का बेहतर मौका होता है। वे सहज रूप से जानते हैं कि विशिष्ट दृष्टिकोणों और द्विआधारी विकल्पों के लिए कोई स्थान नहीं है, जो कि निरर्थक चर्चाओं और वार्तालापों का मुख्य आधार हैं। उदाहरणार्थ, शहरी बनाम ग्रामीण, विकास बनाम समानता या विकास, तथा विनिर्माण बनाम सेवाएं। वे सहज रूप से जानते हैं कि भारत को विकास के लिए कई रास्ते अपनाने की जरूरत है। यह अच्छी बात है। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इस पैमाने पर नहीं। समय-सीमा में नहीं और अशांत वैश्विक वातावरण के बीच भी नहीं। इस प्रयास में सफलता पाने के लिए सरकारों, व्यवसायों और सामाजिक क्षेत्रों के बीच आम सहमति बनाना और उसे कायम रखना आवश्यक है।

कृषि विकास का इंजन बन सकती है यदिण्ण्ण

कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके लिए इस तरह के अखिल भारतीय संवाद की आवश्यकता है। कृषि और किसान किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश देश समझते हैं कि भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत उन्हें पानी, बिजली और उर्वरक पर सब्सिडी देता है। पहले दो चीजें लगभग मुफ्त दी जाती हैं। उनकी आय पर कर नहीं लगता। सरकार 23 चुनिंदा वस्तुओं के लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (**MSP**) प्रदान करती है। पीएम-किसान योजना के माध्यम से किसानों को मासिक नकद सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय सरकारें – राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय – किसानों के ऋण माफ कर देती है। इसलिए, भारत में सरकार किसानों की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए पर्याप्त संसाधन खर्च करती है। फिर भी, यह तर्क दिया जा सकता है कि मौजूदा और नई नीतियों में कुछ बदलाव करके उन्हें बेहतर सेवा दी जा सकती है।

राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा एक-दूसरे के विपरीत उद्देश्यों के लिए काम करने वाली नीतियों के कारण किसानों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है, मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो रही है, भूजल स्तर घट रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन से नदियां और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, फसलों को पोषक तत्वों से वंचित किया जा रहा है और फाइबर और प्रोटीन के बजाय चीनी और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार

के कारण लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। यदि हम कृषि क्षेत्र की नीतियों में व्याप्त गांठों को खोल दें तो इसका लाभ बहुत अधिक होगा। किसी भी अन्य बात से अधिक, इससे सामाजिक-आर्थिक लाभ के अलावा, राष्ट्र को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में राज्य के आत्मविश्वास और क्षमता में विश्वास बहाल होगा।

पहले के विकास मॉडलों में अर्थव्यवस्थाओं को कृषि से शुरू होकर औद्योगिकीकरण और फिर मूल्य-संवर्धित सेवाओं की ओर विकास यात्रा में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया था। तकनीकी प्रगति और भूराजनीति इस पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दे रही है। व्यापार संरक्षणवाद, संसाधन-जमाखोरी, अतिरिक्त क्षमता और डंपिंग, उत्पादन को स्थानीय स्तर पर ले जाना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का आगमन, देशों के लिए विनिर्माण और सेवाओं से विकास को बाहर निकालने की गुंजाइश को कम कर रहा है। यह हमें पारंपरिक ज्ञान को उलटने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या कृषि क्षेत्र उद्धारक हो सकता है? खेती के तौर-तरीकों और नीति निर्माण के मामले में जड़ों की ओर लौटना, कृषि से उच्च मूल्य संवर्धन उत्पन्न कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है, खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात के अवसर पैदा कर सकता है और कृषि क्षेत्र को भारत के शहरी युवाओं के लिए फैशनेबल और उत्पादक बना सकता है। वर्तमान नीति विन्यास के कारण पिछले कुछ वर्षों में उत्पन्न उपरोक्त समस्या क्षेत्रों का समाधान हो जाने पर वे भारत की शक्ति के स्रोत बन सकते हैं तथा शेष विश्व -विकासशील एवं विकसित दोनों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं ।

छोटे उद्यमों को उन्मुक्त करना

एक अन्य क्षेत्र जहां नीतिगत इरादे अभी तक वांछित परिणामों में प्रकट नहीं हुए हैं, वह है लघु, मध्यम और बड़े उद्यम। पहले कई उत्पाद लघु उद्योगों के लिए आरक्षित थे। लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि इससे न तो लघु उद्योगों को लाभ हो रहा था और न ही समग्र अर्थव्यवस्था को। हाल ही में उन्हें औपचारिक बनाने के लिए किए गए ठोस प्रयासों से प्रगति हो रही है। वित्त तक पहुंच के मामले में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। क्रेता और ऋणदाता पुरानी मानसिकता और प्रथाओं को इतनी धीमी गति से त्याग रहे हैं कि इन उद्यमों को इसका प्रभाव महसूस नहीं हो पा रहा है। हालांकि, इन उद्यमों को कानून अनुपालन के बोझ से अधिकतम राहत की आवश्यकता है जिसका वे सामना करते हैं। कानून, नियम और विनियमन उनके वित्त, क्षमताओं और सीमा को बढ़ाते हैं, या शायद उन्हें बढ़ने की इच्छा से वंचित करते हैं।

सफल ऊर्जा संक्रमण एक ऑर्केस्ट्रा है

ऊर्जा परिवर्तन और गतिशीलता जैसी अन्य प्राथमिकताएं, कृषि क्षेत्र की नीतियों को सही ढंग से लागू करने की जटिलता की तुलना में फीकी पड़ सकती हैं। फिर भी, उनमें एक बात समान है। उन्हें कई मंत्रालयों और राज्यों में कई कामों को संरेखित करने की आवश्यकता होती है । यह सूची बहुत लंबी है।

ऊर्जा संक्रमण और गतिशीलता के मुद्दों पर निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है:

(क) शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों पर संसाधन निर्भरता;

(ख) तकनीकी चुनौतियाँ जैसे विद्युत उत्पादन में रुकावट, अक्षय ऊर्जा स्रोतों और बैटरी भंडारण से उत्पादन में उतार-चढ़ाव के बीच ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना।

(ग) भूमि की कमी वाले देश में भूमि प्रबंधन के अवसर लागत की पहचान;

(घ) राजकोषीय निहितार्थ जिसमें अक्षय ऊर्जा उत्पादन और ई-मोबिलिटी समाधानों के लिए सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय, जीवाश्म ईंधन की बिक्री और परिवहन से वर्तमान में प्राप्त कर और माल ढुलाई राजस्व की हानि शामिल है;

(ङ) तथाकथित 'संकटग्रस्त परिसंपत्तियों' से बैंक बैलेंस शीट को होने वाली हानि और

(च) वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों जैसे सार्वजनिक परिवहन मॉडल आदि के गुणों की जांच।

अन्य देशों की नीति प्रथाओं का अनुकरण करना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय, क्योंकि उन तरीकों और स्थानों से समाधान नहीं निकल सकता, जिन्होंने पहली बार समस्याएं पैदा की थीं।

जाने देना अच्छे शासन का हिस्सा है

आगे आने वाली चुनौतियों पर विचार करते समय किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक भारत का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी है। हमने एक लंबा सफर तय किया है। अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 93 में लगभग 288 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 3ण्6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। भारत ने प्रति डॉलर ऋण पर अन्य तुलनीय देशों के संबंध में अधिक वृद्धि की है। घोर गरीबी लगभग समाप्त हो गई है। मानव विकास सूचकांक में सुधार हुआ है और

अधिक भारतीय, विशेषकर महिलाएँ शिक्षित हो रही हैं। अपनी सभी खामियों और कमियों के बावजूद, इस प्रणाली ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की है, जहाँ कभी-कभार परिपक्व टिप्पणियाँ कारगर साबित होती हैं। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हालांकि, देश को चलाने के लिए एक प्रणाली को मजबूत न करना एक खोया हुआ अवसर होगा, जैसा कि अतीत में कई बार हुआ है, क्योंकि हमारा भविष्य अत्यधिक अनिश्चित हो गया है। वैश्विक स्तर पर लगभग आठ दशकों की सापेक्षिक शांति के बाद, विश्व दीर्घकालिक प्रभाव वाले एक बड़े एवं व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। भारतीय राष्ट्र अपनी क्षमता को उन्मुक्त कर सकता है तथा अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है, ताकि वह उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सके, जहां उसे ऐसा करना आवश्यक है, तथा इसके लिए उसे उन क्षेत्रों पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करनी होगी, जहां उसे ऐसा करना आवश्यक नहीं है। लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं, जो सरकार के सभी स्तरों द्वारा व्यवसायों पर लागू की जाती हैं, एक भारी बोझ है। इतिहास के सापेक्ष, बोझ हल्का हो गया है। लेकिन जहां होना चाहिए था, उसके सापेक्ष, यह अभी भी बहुत भारी है। इसका बोझ उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो इसे उठाने में सबसे कम सक्षम हैं - छोटे और मध्यम उद्यम। यह उन्हें पीछे धकेलता है, उनकी आकांक्षाओं को बाधित करता है और इस प्रक्रिया में देश को भी पीछे धकेलता है। पहली नजर में, ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्थिक विकास दर अच्छी है और प्रगति के स्पष्ट संकेत भी हैं। लेकिन, हम कभी भी इसके विपरीत नहीं जान पाएंगे: "यह क्या हो सकता था"।

ईशोपनिषद हम सभी को अपनी संपत्ति छोड़ देने (त्यागने), स्वतंत्र होने और उस स्वतंत्रता का आनंद लेने का आदेश देता है:

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।

सत्ता सरकारों की एक बेशकीमती संपत्ति है। वे कम से कम कुछ हद तक इसे छोड़ सकते हैं और शासक और शासित दोनों में इसके द्वारा पैदा होने वाले हल्केपन का आनंद ले सकते हैं।

अंत में,ण्ण्ण

उभरती हुई अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों के बीच इस देश को विकसित राष्ट्र बनने के लिए जिस त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है, वह है सरकारें भरोसा करें और जाने दें, निजी क्षेत्र दीर्घकालिक सोच और निष्पक्ष आचरण के साथ भरोसे का प्रतिदान करें तथा जनता अपने वित्त और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में अपने कई अध्यायों में ऊपर चर्चित अनेक मुद्दों को शामिल किया गया है, इसके अलावा पाठकों को सरकारी नीतियों और उनके प्रदर्शन, उनके प्रभावों, नवाचारों, विकास और अनुकरणीय सफलता की कहानियों से भी अवगत कराता है। पहले की तरह, सर्वेक्षण की मुख्य विषय-वस्तु वे अध्याय हैं जो कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हैं।

'आर्थिक कार्य विभाग' के 'अर्थशास्त्र प्रभाग' में हमारे लिए, आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करना तथा उसे आपके हाथों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंचाना, पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए किया जाने वाला कार्य है। समीक्षाधीन वर्ष में देश की प्रगति को रिकार्ड करना और साझा करना तथा इस बात पर विचार करना कि अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए एक सीखने का अनुभव है। ऐसा करते समय, हो सकता है कि हमने कुछ गलतियाँ की हों। कृपया हमें बताएँ। हम वादा करते हैं कि हम इसे और बेहतर बनाने का वादा करते हैं। आखिरकार, यही वह सब है जो हम सभी कर सकते हैं हमें करना चाहिए।

(वी. अनंत नागेश्वरन)
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय, भारत सरकार

आभारोक्ति

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सर्वेक्षण को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की टिप्पणियों और अंतर्दृष्टि से लाभ मिला है। सर्वेक्षण में माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव डॉण टीण वीण सोमनाथन, सचिव आर्थिक कार्य विभाग श्री अजय सेठ, सचिव डीआईपीएएम श्री तुहिन कांता पांडे, सचिव डीपीई श्री अली रजा रिजवी, सचिव वित्तीय सेवाएं श्री विवेक जोशी और राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा के सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया गया है।

आर्थिक प्रभाग और आर्थिक कार्य विभाग के अन्य प्रभागों से सर्वेक्षण में योगदानकर्ताओं में शामिल हैं: चांदनी रैना, एंटनी सिरिएक, अनुराधा गुरु, अनुपा एस नायर, कोकिला जयराम, सैयद जुबैर नकवी, धर्मेंद्र कुमार, सीमा जोशी, हरीश कुमार कलेगा, दीपिका श्रीवास्तव, अमित श्योराण, श्रेया बजाज, मेघा अरोड़ा, दीक्षा सुप्याल बिष्ट, मनोज कुमार मिश्रा, रितिका बंसल, मोहम्मद आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पायने, ईशा स्वरूप, राधिका गोयल , हरीश यादव, राजेश शर्मा, मृत्युंजय कुमार, अमित कुमार केसरवानी, दीपद्युति सरकार, अजय ओझा, केण चंद्र शेखर, रोहित कुमार तिवारी, हेमा राणा, अपराजिता त्रिपाठी, सोनाली चौधरी, भारद्वाज आदिराजू, सुरभि सेठ, मीरा उन्नीकृष्णन, आकाश पुजारी, रोशन यादव, रोहित त्रिवेदी, सत्येन्द्र किशोर, एस रामकृष्णन, विशाल गोरी, कुणाल बंसल, रितेश कुमार गुप्ता, धृति अरोड़ाद्य मुना साह तथा बृजपाल अधिकारियों के निजी कर्मचारी हैं।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में टिप्पणियों और इनपुट के साथ योगदान दिया। उनमें शामिल हैं: राजीव मिश्रा, सोलोमन अरोकियाराज, बलदेव पुरुषार्थ, प्रवाकर साहू, अजय कुमार सूद, अलीशा जॉर्ज, गौरव मसलदान, ई श्रीनिवास, नीतीश सूरी, नीलांभुज शरण, कामखेंथांग गुइटे, एमण्जीण जयश्री, धृजेश कुमार तिवारी, अवदेश कुमार चौधरी, शेफाली ढींगरा, आरण राजेश, योगेश सूरी, कुसुम मिश्रा, बिजय कुमार बेहरा, एण सृजा, पीण्केण अब्दुल करीम, सीण वनलालरामसंगा, रेणुका मिश्रा, माणिक चंद्र पंडित, गायत्री नायर मनोज मधोलिया, सुरजीत कार्तिकेयन, विष्णुकांत पीबी, कपिल पाटीदार, जयपाल, अनुश्री राहा, चितवन ढिल्लन, लीना कुमार, उपदेश शर्मा, प्रभात कुमार सिंह, धरम प्रकाश, दलीप कुमार, अखिलेश शर्मा, एसएन मिश्रा, अंशुमन कामिला, इशिता गांगुली त्रिपाठी, लालसंगलूर, राजश्री रे, अंशू भारद्वाज, राजनाथ राम, ऋषिका चोरारिया, मनीषा सेनसारमा, फैज अहमद किदवई, फ्रैंकलिन एल खोबुंग, ए। प्रतिभा, इंदु बुटानी, वीण्एसण सहरावत, कुशवंत कुमार, राजेश कुमार, साबरी बिन कासिम, शांता शर्मा, राहुल मीना, पुनीत भाटिया, अभय बाकरे, धीरज कुमार श्रीवास्तव, जेण राजेश कुमार, अजय माथुर, अमित प्रोथी, अल्पना साहा, प्रिंस धवन, एंसी मैथ्यू एनण्पीण, एण्आरण रॉय, अश्विनी कुमार, राजकुमार, प्रमोद कुमार आर्य और सुभाष चंद।

हमें कई विशेषज्ञों, उद्योग निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं से भी मदद मिली, जिनमें सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, आईएफएससीए, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, तीर्थंकर पटनायक, संगीता गुप्ता, तनय दलाल, वृंदा बंसोडे, भुवन आनंद, शुभो रॉय, आरण सुब्रमण्यम, सुचिता दत्ता और प्रसन्ना तंत्री शामिल हैं।

मनोज सहाय, अपर्णा भाटिया, जसबीर सिंह, सुश्रुत सामंत, दलीप कुमार, सुनील कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, दवेन्द्र कुमार, नवनीत पाठक, राहुल गोयल तथा आर्थिक कार्य विभाग के अन्य कर्मचारियों द्वारा कार्यक्षम प्रशासनिक सहयोग दिया गया है ।

सर्वेक्षण का हिंदी अनुवाद आर्थिक कार्य विभाग के हिंदी अनुभाग के लेफ्टिनेंट कर्नल एमण्केण सिंह, डॉण पूरन सिंह, हरीश सिंह रावत, रजनीश कुमार, अनुपम आर्य, समता रानी, बबीता गुंजियाल, जिंटू कुमार मंडल, विनय कुमार, कमलेश धमुनया, अर्चना सिंह, माया मीना, शियो पूजन चौधरी, नीरज मिश्रा, गौरव भाटिया, रीना कुमारी मीना, सुरभि, शिखा और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के जय वीर, मीनाक्षी वर्मा, मनीष भटनागर, मनोज कुमार, राजीव कुमार सिंह, दिवाकर शुक्ला, रवीश रंजन, धर्मेंद्र कुमार द्वारा किया गया। सर्वेक्षण का हिंदी संस्करण मिंटो रोड स्थित मुद्रण निदेशालय के अनिल बजाज, हिमांशु शर्मा, जिया लाल मैठाणी, दिनेश दीवान द्वारा टाइप किया गया।

सर्वेक्षण का कवर पेज इज्जुर रहमान के द्वारा डिजाइन किया गया। सिग्नेचर प्रिंटर्स के इज्जुर रहमान, दीपक अग्रवाल, गौतम हलदर और मोहम्मद सुहैल ने सर्वेक्षण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों की पेज सेटिंग की।

आर्थिक सर्वेक्षण इसकी तैयारी में शामिल सभी लोगों के परिवारों के प्रति उनके धैर्य और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

वी. अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार

संकेताक्षर

एएजीआर	औसत वार्षिक विकास दर
एएआई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
एएयू	समनुदिष्ट राशि इकाइयां
एएवाई	अंत्योदय अन्न योजना
एबीसी	अकादमिक ऋण बैंक
एबीडीएम	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
एबीएचए	आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता
एबी–पीएमजेएवाई	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
एबी–आरपीवाई	आत्मनिर्भर भारत रोजगार प्रोत्साहन योजना
एबीआरवाई	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
एबीएस	स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीपी	आकांक्षी जिला कार्यक्रम
एईएस	उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ
एएफएचसी	किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक
एजीईवाई	आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना
एएचआईडीएफ	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
एआई	आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस
एआई	आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस
एआईआईपी	कृत्रिम बुद्धिमत्ता बौद्धिक संपत्ति
एआईबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश कोष
एआईएफ	कृषि अवसंरचना कोष
एआईआईएमएस	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एआईआरएडबल्यूएटी	एआई अनुसंधान विश्लेषण और ज्ञान प्रसार प्लैटफार्म
एआईएसएचई	अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
एआईटीआईजीए	आसियान- भारत माल व्यापार समझौता
एकेआरएसपी	आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम
एएमसीएस	परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां
एएमआई	कृषि विपणन अवसंरचना
एएमआरआईटी	उपचार के लिए सस्ती दवाइयां और विश्वसनीय प्रत्यारोपण
एएमआरयूटी	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन
एपीएएआर	स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एपीआईएस	एक्टिव फर्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स
एपीएलएम	कृषि उपज और पशुधन विपणन

एपीएमसीएस	कृषि उत्पाद विपणन समितियों
एपीएमआर	कृषि उत्पादन विपणन विनियमन
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एआरसीएस	संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
एआरजी	स्वचालित वर्षामापी
एआरएचसी	अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज
एआरआईएमए	ऑटोरेग्रेसीव इंटेग्रटेड मुविंग एव्रेज
एएसबीए	ब्लॉक किए गए खाते द्वारा समर्थित एप्लिकेशन
एएसआई	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
एस्ट्रोसैट	अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला
एटीएफ	एविएशन टरबाईन फ्यूल
एटीपी	स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा
एयूएम	प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां
एडबल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
एडब्ल्यूएस	स्वचालित मौसम स्टेशन
बीबीएसएसएल	भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड
बीडीआई	बाल्टिक शुष्क सूचकांक
बीई	बजट प्राक्कलन
बीएफएसआई	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
बीएफटी	बेयर फूट तकनीशियन
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीआईएम	बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मोडलिंग
बीआईएस	अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक
बीओपी	भुगतान संतुलन
बीपीएम	कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन
बीपीओ	बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
बीआरओ	सीमा सड़क संगठन
बीआरएसआर	व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट
बीएसएफ	ब्लैक सोल्जर फ्लाईज
बीटीएस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन
सीएसीपी	कृषि लागत और मूल्य आयोग
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय
सीबीजी	संपीड़ित जैव गैस
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीएम	कोल बेड मीथेन
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीसी	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन
सीसीएस	कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज

सीसीटी	कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम
सीसीयूएस	कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण
सी-डैक	प्रगत संगणन विकास केंद्र
सीडीएम	स्वच्छ विकास तंत्र
सीडीआरआई	आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीईसीपीए	व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता
सीईपीए	विस्तृत आर्थिक भागीदारी समझौता
सीईआरएस	प्रमाणित उत्सर्जन कटौती
सीईटी-1	कॉमन इक्विटि टियर - 1
सीएफपीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीजीए	महा लेखानियंत्रक
सीजीएस	ऋण गारंटी योजना
सीजीटीएमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सीएचसीएस	कस्टम हायरिंग सेंटर
सीआईसी	चलन में मुद्रा
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीआईपी	केंद्रीय निर्गम मूल्य
सीआईआरपी	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीआईएस	ग्राहक सूचना पत्र
सीकेएम	सर्किट किलोमीटर
सीएमआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र
सीएमएम	कोयला खदान मीथेन
सीएनडी	उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं
सीएनजी	संपीडित प्राकृतिक गैस
सीओटू	कार्बन डाइऑक्साइड
सीओपी	पार्टियों का सम्मेलन
सीओपीएस	पार्टियों का सम्मेलन
सीओआरएसआईए	अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई-सी	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीपीएसयू	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीक्यूजीआर	चक्रवृद्धि तिमाही वृद्धि दर
सीआरएआर	कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशिओ
क्रिसिल	क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीआरओपीआईसी	फसलों के वास्तविक समय का अवलोकन और तस्वीरों का संग्रह
सीआरपी	कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन

सीआरआर	नकद आरक्षित अनुपात
सीएसआईआर	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसएल	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
सीएसओ	नागरिक समाज संगठन
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
सीएसपी	क्लाउड सेवा प्रदाता
सीएसआर	कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीवी	विचलन का गुणांक
सीडब्ल्यूएस	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति
सीडब्लूएसएन	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
डीए-एफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
डीएएचडी	पशुपालन और डेयरी विभाग
डीएपी	डाइ-अमोनियम फॉस्फेट
डीएवाई-एनआरएलएम	दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डे-एनयूएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
डीबीएफओटी	डिजाइन - बिल्ड ख्र फाइनेंस - ऑपरेट - ट्रान्सफर
डीबीआई	डायवर्सन-आधारित सिंचाई
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीयू-जीकेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
डीईएच	निर्यात केंद्र के रूप में जिले
डीएफसी	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
डीएफआई	डिजिटल वित्तीय समावेशन
डीएफआई	किसानों की आय दोगुनी करने की रिपोर्ट
डीजीसीए	नागर विमानन महानिदेशालय
डीजीक्यूआई	डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक
डीआईईटी	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
डीआईकेएसएचए	ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना
डीआईएससीओएम	वितरण कंपनियाँ
डीआईएसएचए	जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितियां
डीओपी	डाक विभाग
डीपीआई	डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
डीपीआईआईटी	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीआरआई	आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना
डीआरआईपी	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना
डीआरटी	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डीएसटी	प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली
डीटीएच	डायरेक्ट टू होम
ईएईयू	यूरेशियन आर्थिक संघ
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीबी	यूरोपीय सेंट्रल बैंक

ईसीसीई	आरंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा
ईसीटीए	आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
ईएफटीए	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ईआई	इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग
ई-एलओजीएस प्लैटफॉर्म	इज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेस प्लैटफॉर्म
ईएमसी	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर
ईएमडीई	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएँ
ईएमआई पेमेंट	समान मासिक किश्त भुगतान
ईएमआई/ईएमसी	विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप/विद्युतचुंबकीय अनुकूलता
एनएएम	राष्ट्रीय कृषि बाजार
ई-एनएएम	ई- राष्ट्रीय कृषि बाजार
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीओएस	इलेक्ट्रोनिक बिक्री केंद्र
ईआर-डी	उद्यम, अनुसंधान, और विकास
ईआरयू	उत्सर्जन घटौती इकाइयाँ
ईएसजी	पर्यावरणीय, सामाजिक और शासनिक
ईएसएस	ऊर्जा भंडारण प्रणाली
ईटीसीए	आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता
ईटीएफ	एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड
ईयू	यूरोपीय संघ
ईयू-ईटीएस	यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना
ईवीज	इलेक्ट्रिक वाहन
ईएक्सआईएम	निर्यात-आयात बैंक
एफएडीए	फेडेरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन
एफएओ	खाद्य एवं कृषि संगठन
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
एफसीआई	भारतीय खाद्य निगम
एफसीआरए	वायदा संविदा विनियमन अधिनियम
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफईडी	फेडरल रिजर्व
एफईआर	विदेश मुद्रा भंडार
एफआईडीएफ	मत्स्य-पालन अवसंरचना विकास निधि
एफएलएफपीआर	महिला श्रम-बल सहभागिता दर
एफएलएन	आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान
एफएमसी	वायदा बाजार आयोग
एफओएमसी	फेडरल ओपन मार्केट कमेटी
एफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
एफपीआई	विदेश पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ	कृषक उत्पादक संगठन

एफपीएस	उचित मूल्य की दुकान
एफआरबी	विदेशी पुनर्बीमा शाखाएं
एफएसए	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन
एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएसएसए	वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन रिपोर्ट
एफएसएसआई	फाइनेंसियल सिस्टम स्ट्रेस इंडिकेटर
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
एफटीके	फील्ड परीक्षण किट
एफटीटीएच	फाइबर टू द होम
एफवाई	वित्त वर्ष
एफवाई	वित्त वर्ष
जीबीएस	जेंडर बजट स्टेटमेंट
जीबीएस	सकल बजटीय सहायता
जीसीए	सकल फसली क्षेत्र
जी.सी.सी.	वैश्विक क्षमता केंद्र
जीसीपी	ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
जीसीटी	गतिशक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईसी	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
जीईएम	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीईआरडी	अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय
जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट
जीएफसीएफ	कुल स्थिर पूंजी निर्माण
जीएचई	स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय
जीएचजी	ग्रीन हाउस गैसें
जीआई क्लाउड	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड
जीईएफटी-सिटी	गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
जीआईआई	वैश्विक नवाचार सूचकांक
जीएनआई	सकल राष्ट्रीय आय
जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्ति
जाओआई	भारत सरकार
जीओवीटी.	सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीएआई	कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर वैश्विक साझेदारी
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
जीपीजी	ग्राम पंचायतें
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसएलवी	भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान

जीएसटी	माल और सेवा कर
जीएसटी	ग्लोबल स्टॉकटेक
जीटी	सकल टनभार
जीटीआर	सकल कर राजस्व
जीवीए	सकल मूल्य वर्धित
जीवीए	सकल मूल्य वर्धित
जीवीसी	वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ
जीडब्ल्यू	गीगावाट
जीडब्ल्यू इक्विवेलेंट	गीगावाट समतुल्य
जीडब्ल्यूएमआर	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचएएल	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
एचएएम	हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल
एचसीईएस	पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण
एचईआई	उच्च शिक्षा संस्था
एचएफसी	आवासीय वित्त कंपनियाँ
एचएचआई	हर्शमैन-हर्फिंडाल इंडेक्स
एचकेकेपी	हर खेत को पानी
एचएमएल	सुसंगत सूची
एचएनआई	हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल
एचआर	मानव संसाधन
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईबीपी मार्ग	इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट
आईसीएओ	अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडीआर	पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं
आईसीडी	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ
आईसीआरआईईआर	भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद
आईसीटी	सूचना व संचार प्रौद्योगिकी
आईडीआरसीएल	इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड
आईईबीआर	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन
आईईटी	अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र
आईएफएससी जीआईएफटी सिटी	इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
आईएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईएचएचएल	भिन्न-भिन्न घरेलू शौचालय
आईआईई	भारतीय उद्यमशीलता संस्थान
आईआईजी	भारतीय निवेश ग्रिड
आईआईपी	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति

आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईआईपीडीएफ	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटीएम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
आईएलआईएमएस	एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली
आईएमसी	इंदौर नगर निगम
आईएमईसी	भारत मध्य-पूर्व यूरोप कोरिडोर
आईएमईएस	अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम
आईएमएँफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस	भारत - जल संसाधन सूचना प्रणाली
इन्फ्रा	अवसंरचना
आईएन-एसपीएसीई	भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र
आईएनएसटीसी	अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा
आईएनवीआईटीज	अवसंरचना निवेश न्यास
आईओटी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आईपीओ	इनिशियल पब्लिक ऑफर
आईआर	भारतीय रेल
आईआरसीटीसी	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
आईआरएफसी	भारतीय रेल वित्त निगम
आई आर आई एस	लचीले द्वीपीय राज्यों के लिए अवसंरचना
आईएसए	अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
आईएसएएम	एकीकृत कृषि विपणन योजना
आईएसआरओ	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीएमओज	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम
आईवीए	स्वतंत्र सत्यापन अभिकरण
आईडब्ल्यूएआई	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
आईडब्ल्यूटी	अंतर्देशीय जल परिवहन
जेएएम	जन धन-आधार-मोबाइल
जेईई	संयुक्त प्रवेश परीक्षा
जेजेएम	जल जीवन मिशन
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह
जेएसएस	जन शिक्षण संस्थान
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केएलडी	किलोलीटर प्रति दिन
केपी	क्योटो प्रोटोकोल
कृषि-डीएसएस	कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली
केडब्ल्यूएच	किलोवाट्ट घंटा
एलएंडटी	लार्सन एंड टुब्रो

एलएएमए	लॉग एनलिटिक्स एंड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन
एलएएमपी	वृहत क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सोसायटी
एलसीएएफ	लोअर कार्बन एविएशन फ्यूल्स
एलसीओई	बिजली की स्तरीकृत लागत
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
लीडआईटी	लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन
एलईएडीएस	लोजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स
एलईडी	प्रकाश उत्सर्जक डायोड
एलईडीपी	आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एलएचएंडीसी	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण
एलआईएॅफई	पर्यावरण के लिए जीवनशैली
एलएमटी	लाख मीट्रिक टन
एलपीएआई	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
एलपीजी	तरल पेट्रोलियम गैस
एलपीआई	लॉजिस्टिक परफोर्मेंस इंडेक्स
एलटी	लाख टन
एलटीडी.	लिमिटेड
एलटी-एलईडीएस	दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति
एलवीएम3	प्रक्षेपण यान मार्क-3
एम एंड ए	विलय और अधिग्रहण
एमएएचएसआर	मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल
एमएआईएस	बाजार पहुँच पहल योजना
एमएएम	मध्यम तीव्र कुपोषण
एमएएनएएस	मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्थिति संवर्धन प्रणाली
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए	मॉडल कन्सेशन अग्रीमेंट
एमसीएक्स	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
एमईडीपी	सूक्ष्म उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं
एमएफ	म्यूच्यूअल फंड
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमआईएफ	सूक्ष्म सिंचाई निधि
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएमएलपी	मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
एमएमटी	मिलियन मीट्रिक टन
एमएनआरई	बहुराष्ट्रीय उद्यम
एमओएएफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
एमओई	शिक्षा मंत्रालय

एमओएचयूए	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
एमओओसी	व्यापक खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम
एमओपी	म्यूरियेट ऑफ पोटाश
एमओआरटीएच	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओवीसीडीएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमपीसीई	प्रति व्यक्ति मासिक व्यय
एमपीआई	बहुआयामी निर्धनता सूचकांक
एमआरएल	प्रमुख रेल संपर्क
एमआरएल	प्रमुख ग्रामीण संपर्क
एमआरओ	मरम्मत अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल
एमएससीएस	बहु-राज्य सहकारी संस्थाएं
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसपी	खनिज सुरक्षा भागीदारी
एमटीसीओ2ई	मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य
एमटीएम	विपणन हेतु चिह्नित
एमटीओई	मिलियन टन तेल समतुल्य
एमटीपीए	मिलियन टन प्रति वर्ष
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एमडब्लूईक्यू	मेगा वाट समतुल्य
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएडीसीपी	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
नेफेड	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना
एनएपीएस	राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना
एनएआरसीएल	राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.
एनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
एनएएस	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
एनएएसएससीओएम	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
एनएवीएलसी	नेवीगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसीज	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीएपी-2016	राष्ट्रीय नागर विमानन नीति
एनसीसीएफ	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ
एनसीडीसी	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

एनसीडीईएक्स	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज
एनसीईएल	राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफ-एसई	विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा
एनसीआईपी	राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनसीओएल	राष्ट्रीय सहकरी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
एनसीक्यूजी	नया सामूहिक प्रमात्रीकृत लक्ष्य
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरएफ	राष्ट्रीय ऋण ढांचा
एनसीएस	राष्ट्रीय कैरियर सेवा
एनसीटीएफ	राष्ट्रीय व्यापार सुविधाकरण समिति
एनसीवीईटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
एनडीए	अप्रकटीकरण अनुबंध
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनडीएलएम	राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन
एनडीटीएसपी	राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति
एनईईआर	नामिक प्रभावी विनिमय दर
एनईईटी	राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनईपी	राष्ट्रीय बिजली योजना
एनएफए	शुद्ध विदेशी परिसंपत्तियां
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएफएसएम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एनएफएसएम-ओएस-ओपी	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- तिलहन एवं पाम ऑयल
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनआईडीएचआई	राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस
एनआईईएसबीयूडी	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान
एनआईआई	शुद्ध ब्याज आय
एनआईएम	शुद्ध ब्याज उपांत
एनआईपी	नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनएलबीसी	नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एनएलपी	राष्ट्रीय रसद नीति

एनएमसीई	नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
एनएमसीजी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
एनएमएचएस	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएमपी	राष्ट्रीय मुद्रीकरण प्रक्रिया
एनएमएसए	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन
नॉन-कन्वेंशनल	गैर-पारंपरिक
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीडीडी	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
एनपीके	नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम
एनपीपी	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन योजना
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसआईएल	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा
एनएसएसओ	नेशनल सिंगल साइन-ऑन
एनएसटीआई	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान
एनएसवीए	नारी शक्ति वंदन अधिनियम
एनटीआर	गैर-कर राजस्व
एनडब्ल्यूज	राष्ट्रीय जलमार्ग
ओएंडएम	प्रचालन और रखरखाव
ओसीईएन	ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क
ओसीएमएस	ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली
ओडीए	शासकीय विकास सहायता
ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्ति
ओडीओपी	एक जिला एक उत्पाद
ओडीआर	ऑनलाइन विवाद समाधान
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओईएम	मूल उपकरण विनिर्माता
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएफपीओ	ऑफ-फार्म उत्पादक संगठन
ओएफएसटीईडी	ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन, चिल्ड्रन सर्विसेज एंड स्किल्स
ओआई	अन्य मध्यक्षेप
ओएनडीसी	ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स
ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
ओएनओआरसी	एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
ओओआई	अन्य प्रचालनिक आय
ओएसओडब्लूओजी	एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड
ओटीसी	ओवर-द-काउंटर
पीए	अनंतिम वास्तविक आंकड़े
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

पीएआर	परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी रिपोर्टिंग
पीएआरएकेएच (परख)	परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनलिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डवलपमेंट
पीएआरआईवीईएसएच (परिवेश)	प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉंसिव फेसिलिटेशन बाइ इंटरैक्टिव, वर्चुअस एंड एन्वायरनमेंट सिंगल विंडो हब
पीएटी	कर के बाद लाभ
पीएटी	निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार
पीएटी	पोषण भी पढाई भी
पीसीआई	प्रति व्यक्ति आय
पीडीएमसी	पर ड्रॉप मोर क्रॉप
पीई	अनंतिम अनुमान/प्राक्कलन
पीएफसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीएफएम एस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएफआरएआई	भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएचएच	प्राथमिकता वाले परिवार
पीआईबी	पत्र सूचना कार्यालय
पीकेवीवाई	परम्परागत कृषि विकास योजना
पीएलएफएस	आवधिक श्रम-बल सर्वेक्षण
पीएलआई	उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन
पीएलआई योजना	उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
पीएलआईएसएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
पीएम-पोषण	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण
पीएम-स्वनिधि	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
पीएम-आशा	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
पीएम-आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमएवाई-यू	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमएफएमई	पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण
पीएमजी	परियोजना निगरानी समूह
पीएमजीकेएवाई	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएमजीकेवाई	पीएम गरीब कल्याण योजना
पीएमजीएस-एनएमपी	पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमआई	क्रय प्रबंधक सूचकाकं
पीएमजेजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमजेजेवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
पीएम-किसान	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
पीएमकेएमवाई	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएम-केयूएसयूएम् (कुसुम)	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीएम-पीआरएएनएएम (प्रणाम)	पीएम-धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार कार्यक्रम
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएम-श्री	उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल
पीएम-एसवाईएम	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन
पीओएल	पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रिकेंट
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी भागीदारी
पीपीपीएसी	सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति
पीआरएजीएटी(प्रगति)	सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन
पीआरएएसएडी (प्रसाद)	तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान
पीआरएवाईएजी (प्रयाग)	यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के वास्तविक समय विश्लेषण के लिए मंच
पीएसएफ	मूल्य स्थिरीकरण कोष
पीएसएलवी	ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान
पीएसपी	पम्प्ड स्टोरेज परियोजना
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पीवी	फोटोवोल्टिक
पीवीटीण	निजी
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
क्यूआईपी	अर्हित संस्थागत प्लेसमेंट
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरएडी	वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास
आरबीसीएफ	जोखिम-आधारित पूंजी ढांचा
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीएसएफ	जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी ढांचा
आरसीएस	क्षेत्रीय संपर्क योजना
आरडीएन	पोषक तत्वों की अनुशंसित खुराक
आरडीएसएस	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना
आरई	अक्षय ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा)
आरई	संशोधित अनुमान
आरईईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरईई	रेयर अर्थ एलिमेंट्स
आरईआईटी	रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
आरईएन21	21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क
आरईआरए	भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम
आरएफ परीक्षण	रेडियो आवृत्ति परीक्षण
आरएफआईडी	रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन
आरजीएम	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आरआईएस	अनुसंधान और सूचना प्रणाली
आरकेएम	मार्ग किलोमीटर
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरएमबीएस	आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियाँ

आरएमएस	रबी विपणन सीजन
आरओए	परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी पर लाभांश
आरपीएल	रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग
आरआरटीएस	रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
आरएसईटीआई	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीसी	चौबीस घंटे
एसएएएस	सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर
एसएएटीएचआई	आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली
एसए एफ	संधारणीय विमानन ईंधन
एसए एम	गंभीर तीव्र कुपोषण
एसएएमएआरटीएच	ताप विद्युत संयंत्र में कृषि-अवशेषों के उपयोग पर संधारणीय कृषि मिशन
एसएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना
एसएआरएफएईएसआई	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
एसबीएम-जी	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीएम	स्मार्ट सिटी मिशन
एस सी ओ	शंघाई सहयोग संगठन
एस सी आर ए	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम
एसडीएफ	स्टैंडिंग डिपाजिट फैसिलिटी
एसडीजी	संधारणीय विकास लक्ष्य
एसडीएससी-एसएचएआर	सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसईडब्ल्यूए	स्व-नियोजित महिला संघ
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफएसी	लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ
एसएफबी	लघु वित्त बैंक
एसएफटी	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन
एसएचसी	सेकेंडरी हेल्थकेयर सेंटर
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचजी-बीएलपी	एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम
एसआईबी	व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक
एसआईडीबीआई	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआईआईसी	स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
एसकेयू	स्टॉक कीपिंग यूनिट्स
एसएलआर	सांविधिक तरलता अनुपात
एसएमएएम	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन
एसएमआर	स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर
So_2	सल्फर डाइऑक्साइड
एसपी	विशेष परियोजनाएँ
एसपीईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक अवयव और सेमीकंडक्टर विनिर्माण संवर्द्धन योजना

एसपीएस	सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी
एसपीएसई	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसआरबी	जन्म के समय लिंगानुपात
एसआरओ	स्व-विनियामक संगठन
एसआरएस	स्पेक्ट्रम विनियामक सैंडबॉक्स
एसएसई	सोशल स्टॉक एक्सचेंज
एसएसएलवी	लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान
एसटीएआरएस	राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ करना
एसटीईएम	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित
एसटीपी	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
एसटीटी	अल्पकालिक प्रशिक्षण
एसवीएएमआईटीवीए	गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण
एसवीईपी	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम
एसडब्ल्यएएमआईएच	किफायती और मध्यम आय वाले आवासन के लिए विशेष विंडो
एसडब्ल्यूएवाईएएम	स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स
एसडब्ल्यूआईएफटी	व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस
टीएएस	लेन-देन सलाहकार
टीबीटी	व्यापार में तकनीकी बाधाएँ
टेलीकॉम	दूरसंचार
टीईपीए	व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता
टीएचई	कुल स्वास्थ्य व्यय
टीआईईएस	निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना
टीपीए	त्रिपक्षीय समझौता
टीपीडी	टन प्रति दिन
टीआरईडीएस	व्यापार प्राप्य छूट परिदान प्रणाली
टीटीडीआई	यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक
यूएई	संयुक्त अरब अमीरात
यूडीएएएन (उडान)	उड़े देश का आम नागरिक
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएचडब्ल्यूसी	शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
यूजेएएलए	सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति
यूएलबीएस	शहरी स्थानीय निकाय
यूएलआईपी	एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म
यूएलएलएएस	समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम बोध
यूएलपीआईएन	विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या
यूएमएएनजी	नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईएससीएपी	एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग

यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन
यूएनएफपीए	जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यूपीएचसी	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
यूआर	बेरोजगारी दर
यूआरपी	उद्यम पंजीकरण पोर्टल
यूएसडी	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर
यूएसओएफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यूटी	संघ राज्यक्षेत्र
यूवी	उपयोगिता वाहन
वीबीएसवाई	विकसित भारत संकल्प यात्रा
वीसीएम	स्वैच्छिक कार्बन बाजार
वीजीएफ	वायबिलिटी गैप फंडिंग
वीआईजेड	विडेरे लिसेट (अर्थात)
वीआरआर	परिवर्तनीय रेपो दर
वीआरआरआर	वेरियबल रेट रिर्वस रेपो
डबल्यूएएसएच	जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य
डब्ल्यूईएफ	विश्व आर्थिक मंच
डब्ल्यूईओ	वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
वाई-फाई	वायरलेस फिडेलिटी
डबल्यूआईएनडीएस	मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
डबल्यूआईएसई-केआईआरएएन	विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ - अनुसंधान उन्नति में ज्ञान की भागीदारी
डब्ल्यूआईटीई-जोन	वायरलेस परीक्षण क्षेत्र
डब्ल्यूआईटीएस	विश्व एकीकृत व्यापार समाधान
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूपीआर	कामगार जनसंख्या अनुपात
डब्ल्यूक्यूएमआईएस	जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली
डब्ल्यूएसए	मार्ग-पार्श्विक सुविधाएं
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
येस-टेक	प्रौद्योगिकी के आधार पर उपज का अनुमान
वाईओवाई	वर्ष-दर-वर्ष
जेडसीजेडपी	जीरो कूपन जीरो प्रिन्सिपल

तालिकाओं की सूची

तालिका सं.	तालिका	पृष्ठ सं.
तलिका I.1	महामारी से प्रेरित संकुचन के बाद से तेज वृद्धि	15
तलिका I.2	केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय का व्यापक आधार पर परिनियोजन (मान हजार करोड़ रुपये में)	20
तालिका II.1	घरेलू ऋण और जमा दरों में संचरण में तेजी	38
तालिका II.2	वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा के संकेतकों में भारत का प्रदर्शन	50
तालिका II.3	वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा पैरामीटरो की क्रास-कंट्री तुलना	50
तालिका II.4	भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र है	54
तालिका II.5	विभिन्न देशों में बाजार पूंजीकरण से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात	59
तालिका IV.1	भारत के व्यापार के प्रमुख पहलू	97
तालिका IV.2	सेवा व्यापार का लचीला प्रदर्शन	107
तालिका IV.3	भारत के प्रमुख विदेशी ऋण संकेतक: स्थिरता का संक्षिप्त विवरण	138
तालिका VI.1	भारत में कार्बन बाजार की संस्थागत संरचना	186
तालिका VII.1	सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा व्यय में रुझान	196
तालिका VII.2	प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं	206
तालिका VII.3	भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	211
तालिका VII.4	स्कूली शिक्षा में सरकारी पहल	219
तालिका VII.5	स्कूल के बुनियादी	223
तालिका VII.6	विभिन्न श्रेणियों से उच्च शिक्षा में नामांकन	226
तालिका VII.7	ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता	239
तालिका VII.8	एमजीएनआरईजीएस पर प्रमुख संकेतक	241
तालिका VIII.1	भारतीय कारखाने प्रतिस्पर्धी प्रति-श्रमिक स्थान मानकों को अपनाकर अधिक श्रमिकों को काम पर रख सकते हैं	270
तालिका VIII.2	कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रगति	291
तालिका X.1	कोयले के उत्पादन, खपत और आयात में वृद्धि	329
तालिका X.2	फेम योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत प्रोत्साहित वाहनों की संख्या	338
तालिका X.3	ऋण परिनियोजन में उद्योग-वार वृद्धि	344
तालिका X.4	भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथ्य: वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21 औसत	345
तालिका XI.1	यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, 2024 में भारत की रैंकिंग 39 हुई	363
तालिका XII.1	अवसंरचना से संबंधित एफडीआई: प्रमुख अनुपात	383

चार्ट की सूची

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट I.1	विकास: संदर्भ मायने रखता है वैश्विक अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति	2
चार्ट I.2	वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा मजबूत वृद्धि दर्ज किया जाना	3
चार्ट I.3	सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं महामारी-पूर्व जीडीपी स्तर को पार कर चुकी है	4
चार्ट I.4	वैश्विक पीएमआई भी मजबूत विकास गति की पुष्टि करता है	4
चार्ट I.5	वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव में कमी	5
चार्ट I.6	अक्टूबर 2023 से भू-राजनीतिक जोखिम धारणाएं नरम हो गई हैं	5
चार्ट I.7	विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है	5
चार्ट I.8	नीतिगत दरें ऊंची रही	5
चार्ट I.9	वैश्विक कमोडिटी सूचकांकों में नरमी	6
चार्ट I.10	अमेरिकी यील्ड कर्व का उलटा होना, जो ब्याज दरों में कटौती की बढ़ी हुई उम्मीद को दर्शाता है	7
चार्ट I.11	अमेरिका में राष्ट्रीय वित्तीय स्थितियाँ बेहतर हुई हैं	7
चार्ट I.12	विभिन्न देशों में राजकोषीय घाटा बढ़ा	7
चार्ट I.13	2023 में वैश्विक ऋण में बढ़ोतरी	7
चार्ट I.14	2023 में व्यापारिक वृद्धि में गिरावट आई	8
चार्ट I.15	एफडीआई प्रवाह में भी कमजोर वृद्धि दर्ज की गई	8
चार्ट I.16	आर्थिक विकास में गति को आगे बढ़ाना	9
चार्ट I.17	व्यापक-आधारित विकास	9
चार्ट I.18	निवेश से विकास को बढ़ावा मिलने के कारण निजी खपत स्थिर	9
चार्ट I.19	महामारी के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की बिक्री में अच्छी वृद्धि हुई है	10
चार्ट I.20	उत्पादक क्षमता निर्माण पर सामान्य सरकार का अधिक ध्यान	11
चार्ट I.21	निजी पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि	11
चार्ट I.22	भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में घरेलू बचत में वृद्धि	11
चार्ट I.23	शीर्ष 8 शहरों में रिकॉर्ड आवास बिक्री	11
चार्ट I.24	निवेश मांग को पूरा करने वाले एससीबी	12
चार्ट I.25	बड़ी कंपनियां कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का लाभ उठा रही है	12
चार्ट I.26	जीडीपी में महामारी से पहले की स्थिति में सुधार	13
चार्ट I.27	प्रवृत्ति से अंतर में लगातार कमी	13
चार्ट I.28	उत्पादन क्षमता में कोई स्थायी हानि नहीं	13
चार्ट I.29	कोई स्थायी उपभोग हानि नही	13
चार्ट I.30	निवेश में उछाल आया है	14
चार्ट I.31	औद्योगिक जीवीए महामारी से पहले की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है	14
चार्ट I.32	सेवाओं का जीवीए पिछड़ रहा है	14
चार्ट I.33	लगातार घटता घाटा अनुपात	16
चार्ट I.34	राजकोषीय घाटे का विघटन निवेश उन्मुखीकरण में वृद्धि दर्शाता है	16
चार्ट I.35	कर और गैर-कर राजस्व दोनों से प्रेरित राजस्व प्राप्तियों में लगातार वृद्धि	16
चार्ट I.36	मजबूत प्रत्यक्ष कर वृद्धि से सकल कर राजस्व में जीडीपी अनुपात में वृद्धि	16
चार्ट I.37	वित्त वर्ष 23 और कोविड-पूर्व स्तर की तुलना में करों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई	17
चार्ट I.38	मजबूत ई-वे बिल उत्पादन मजबूत आर्थिक विकास गति की पुष्टि करता है	17
चार्ट I.39	व्यय का विवेकपूर्ण प्रबंधन	18

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट I.40	केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय और जीडीपी अनुपात में वृद्धि	18
चार्ट I.41	उत्पादक व्यय को प्राथमिकता देना	19
चार्ट I.42	व्यय की गुणवत्ता में सुधार	19
चार्ट I.43	राज्य का जीएफडी जीडीपी के 3 प्रतिशत के निशान से नीचे	21
चार्ट I.44	राज्यों के व्यय की गुणवत्ता में सुधार	21
चार्ट I.45	राज्यों की कुल बकाया देनदारियाँ सकल घरेलू उत्पाद का % की दर से घट रही है	21
चार्ट I.46	राज्यों को अंतरण की प्रगतिशील प्रकृति	22
चार्ट I.47	राज्यों के कर संबंधी प्रयास	22
चार्ट I.48	राज्यों का कुल व्यय	22
चार्ट I.49	राज्यों का राजकोषीय घाटा	22
चार्ट I.50	सामान्य सरकारी देनदारियों और जीडीपी का अनुपात वित्त वर्ष 21 में अपने चरम से नीचे आ गया	23
चार्ट I.51	प्राथमिक घाटा कम हुआ, तथा विकास-ब्याज दर अंतर सकारात्मक बना रहा	23
चार्ट I.52	घटती हुई मुख्य मुद्रास्फीति लेकिन अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति	24
चार्ट I.53	भारत एक उच्च-विकास और निम्न-मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था है	24
चार्ट I.54	वित्त वर्ष 2024 में सीएडी घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 0ण्7 प्रतिशत रह गया	26
चार्ट I.55	एफपीआई प्रवाह ने सीएडी को वित्तपोषित करने और विदेशी मुद्रा भंडार बनाने में सहायता की	26
चार्ट I.56	अप्रैल 2023 से जून 2024 तक रुपया सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक था	26
चार्ट I.57	लगभग 11 महीने के आयात को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार	26
चार्ट I.58	बाह्य अनिश्चितता में वृद्धि के बावजूद मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में कमी	27
चार्ट I.59	विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत उनकी शुरुआत से लाभार्थियों की संख्या	30
चार्ट I.60	बेरोजगारी दर में गिरावट और श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार	30
चार्ट I.61	ग्रामीण-शहरी असमानता में कमी	31
चार्ट I.62	बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा दर्शाई गई जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है	31
चार्ट II.1	आरक्षित मुद्रा (एम0) में वृद्धि में नरमी	35
चार्ट II.2	ब्रॉड मनी (एम3) में वृद्धि	36
चार्ट II.3	वित्त वर्ष 24 में उच्च मनी मल्टीप्लायर, जो बाजार में अधिक तरलता का संकेत देता है	36
चार्ट II.4(क)	तरलता की स्थिति	37
चार्ट II.4(ख)	पॉलिसी कॉरिडोर और ओवरनाइट कॉल मनी दर	37
चार्ट II.5	एससीबी द्वारा ऋण वितरण में दोहरे अंकों की वृद्धि	39
चार्ट II.6	विभिन्न क्षेत्रों में बैंक ऋण में व्यापक वृद्धि	41
चार्ट II.7(क)	एससीबी के जीएनपीए में गिरावट	42
चार्ट II.7(ख)	सीआरएआर आवश्यक मानदंडों से काफी ऊपर	42
चार्ट II.8(क)	परिसंपत्तियों पर रिटर्न (वार्षिकीकृत)	43
चार्ट II.8(ख)	इक्विटी पर रिटर्न (वार्षिकीकृत)	43
चार्ट II.9	एससीबी का उच्च शुद्ध ब्याज मार्जिन	43
चार्ट II.10(क)	अनुमोदित समाधान योजना के माध्यम से सुलझाए गए मामलों की संख्या	46
चार्ट II.10(ख)	लेनदारों द्वारा वसूली	46
चार्ट II.11	ग्रामीण एमएफआई उधारकर्ताओं की बढ़ती हिस्सेदारी	55
चार्ट II.12	पिछले कुछ वर्षों में एमएफआई द्वारा ऋण वितरण में वृद्धि	55
चार्ट II.13	भारतीय शेयर बाजार का उल्लेखनीय प्रदर्शन	58
चार्ट II.14	एसआईपी निवेश में वृद्धि	61
चार्ट II.15	भारतीय वित्तीय प्रणाली में तनाव में कमी एफएसएसआई में परिलक्षित हुई	73

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट II.16	वित्तीय क्षेत्रों में तनाव के स्तर में व्यापक गिरावट	73
चार्ट III.1	2023 में भारत की मुद्रास्फीति ईएमडीईएस से कम	76
चार्ट III.2	ईएमडीईएस की तुलना में एई की मुद्रास्फीति कम होती है	76
चार्ट III.3	भारत अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब है	74
चार्ट III.4	भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य से सबसे कम औसत विचलन (2021-2023) है	74
चार्ट III.5	महामारी के बाद से खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में सबसे कम थी	78
चार्ट III.6	हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृत्ति	78
चार्ट III.7	'वस्त्र और जूते' और 'ईंधन और बिजली' समूहों ने वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति दर में पर्याप्त गिरावट देखी	79
चार्ट III.8	वित्त वर्ष 24 में घटता वैश्विक ऊर्जा सूचकांक	79
चार्ट III.9	कीमत में कटौती/सब्सिडी के कारण एलपीजी मुद्रास्फीति दर में कमी	79
चार्ट III.10	कीमत में कमी के उपयों के कारण पेट्रोल और डीजल की मुद्रास्फीति दर में गिरावट	79
चार्ट III.11	कोर मुद्रास्फीति का इसके घटकों में विभाजन	80
चार्ट III.12	वित्त वर्ष 2024 में कोर मुद्रास्फीति 4 साल के निचले स्तर पर आ गई	80
चार्ट III.13	कोर मुद्रास्फीति को कम करने में मौद्रिक नीति संचालन स्पष्ट है	80
चार्ट III.14	वित्त वर्ष 2024 में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति का योगदान महामारी से पहले की तुलना में कम रहा	81
चार्ट III.15	कम आवास किराया के कारण कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति 9 वर्ष में सबसे कम	81
चार्ट III.16	।म् में लगातार कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति का जोखिम	82
चार्ट III.17	उपभोक्ता टिकाऊ मुद्रास्फीति पूर्व-महामारी स्तर लेवल पर बंद	82
चार्ट III.18	सोने और कपड़े की कीमतों में वृद्धि ने टिकाऊ वस्तुओं में मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया	82
चार्ट III.19	(क) और (ख): परिवहन घटक में गिरावट के कारण कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ मुद्रास्फीति में कमी आई	83
चार्ट III.20	खाद्य मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों का योगदान	84
चार्ट III.21	सब्जियों, दालों और मसालों में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दर	84
चार्ट III.22	वैश्विक और घरेलू खाद्य तेल की कीमतों का सह-संचलन	86
चार्ट III.23	चीनी पर निर्यात प्रतिबंध से भारत में चीनी की कीमतें स्थिर हो गई	86
चार्ट III.24	वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति (%) में अंतरराज्यीय बदलाव	87
चार्ट III.25	वित्त वर्ष 24 में ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति अंतर में अंतरराज्यीय बदलाव	88
चार्ट III.26	ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर में अंतरराज्यीय भिन्नताएं अधिक है	88
चार्ट III.27	उच्च मुद्रास्फीति दर वाले राज्य व्यापक ग्रामीण-शहरी अंतर दिखाते हैं	88
चार्ट III.28	2025 में वैश्विक वस्तु की कीमतों में प्रत्यशित गिरावट	89
चार्ट IV.1	वैश्विक वस्तु व्यापार में वृद्धि: वास्तविक और पूर्वानुमान	95
चार्ट IV.2	बढ़ती व्यापार खुलापन संबंधी संकेतक	97
चार्ट IV.3	वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी	98
चार्ट IV.4	पिछले दस वर्षों में भारत का समग्र व्यापार प्रदर्शन	98
चार्ट IV.5	भारत का वस्तु व्यापार प्रदर्शन	99
चार्ट IV.6	विभिन्न वर्गीकरणों में वस्तु निर्यात की संरचना	100
चार्ट IV.7	भारत के खिलौनों के निर्यात और आयात में रुझान	101
चार्ट IV.8	बढ़ता रक्षा निर्यात	102
चार्ट IV.9	फुटवियर निर्यात में रुझान	102
चार्ट IV.10	बढ़ता घरेलू उत्पादन, घरेलू मांग ओर स्मार्टफोन का निर्यात	103
चार्ट IV.11	भारत के निर्यात लक्ष्य	104
चार्ट IV.12	विभिन्न वर्गीकरणों में व्यापारिक वस्तुओं के आयात की संरचना	105
चार्ट IV.13	पिछले दस वर्षों में भारत के सेवा व्यापार का उल्लेखनीय प्रदर्शन	106

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट IV.14	भारत में जीसीसी की उल्लेखनीय वृद्धि	108
चार्ट IV.15	सकल व्यापार में जीवीसी से संबंधित व्यापार की बढ़ती हिस्सेदारी	111
चार्ट IV.16	जीवीसी से संबंधित व्यापार में विभिन्न विनिर्माण उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी	111
चार्ट IV.17	जीवीसी से संबंधित व्यापार में विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी	112
चार्ट IV.18	शुद्ध पिछड़ी जीवीसी भागीदारी की हिस्सेदारी में वृद्धि	112
चार्ट IV.19	भारत के डवेल टाईम में कमी	120
चार्ट IV.20	वित्त वर्ष 24 के दौरान सीएडी में सुधार	121
चार्ट IV.21	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष: भारत बनाम चुनिंदा देश	121
चार्ट IV.22	भारत 2023 में विश्व में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा	122
चार्ट IV.23	उच्चतर प्रेषण से माल व्यापार घाटे की भरपाई होगी और सीएडी स्थिर होगा	123
चार्ट IV.24	आगे इस सहसंबंध की पुष्टि करती है, क्योंकि तेल की कीमतों में वृद्धि की अवधि उच्च प्रेषण से जुड़ी होती है	124
चार्ट IV.25	भारतीय रुपये/अमेरिकी डालर और प्रेषण का सकारात्मक संघ	124
चार्ट IV.26(क)	भारत में निवल एफपीआई प्रवाह	125
चार्ट IV.26(ख)	वित्त वर्ष 24 के दौरान उभरते बाजार के साथियों के बीच निवल इक्विटी प्रवाह	125
चार्ट IV.27(क)	प्रत्यावर्तन में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 24 में निवल एफडीआई प्रवाह में कमी	126
चार्ट IV.27(ख)	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवल एफडीआई प्रवाह में गिरावट	126
चार्ट IV.28	उद्योग और सेवाओं दोनों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में प्रवृत्ति	127
चार्ट IV.29(क)	कुल एफडीआई में वास्तविक और डिजिटल एफडीआई का हिस्सा	128
चार्ट IV.29(ख)	टेक स्टार्ट-अप में वैश्विक पूंजी प्रवाह	128
चार्ट IV.30(क)	भविष्य के एफडीआई अंतर्वाह के भविष्यवक्ता के रूप में निवेश का लक्ष्य	128
चार्ट IV.30(ख)	एफडीआई प्रवाह और सभी क्षेत्रों के एफडीआई की एकाग्रता के बीच सकारात्मक सहसंबंध	128
चार्ट IV.31	भारत ने वित्त वर्ष 24 में विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है	132
चार्ट IV.32	भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता: अंतर-राष्ट्र परिप्रेक्ष	132
चार्ट IV.33	रुपया/अमेरिकी डालर विनिमय दर की अस्थिरता	133
चार्ट IV.34	वित्त वर्ष 24 में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अन्य देशों की विनिमय दर में अस्थिरता	133
चार्ट IV.35	वित्त वर्ष 24 के दौरान आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्राओं की निवल खरीद (+) और बिक्री (-) संबंधी रुझान	134
चार्ट IV.36	40-मुद्रा एनईईआर और आरईईआर (व्यापार-आधारित भार) के सूचकांक का उतार-चढ़ाव	134
चार्ट IV.37(क)	निवल आईआईपी और जीडीपी के प्रतिशत के रूप मे	137
चार्ट IV.37(ख)	आस्ति देनदारियों का अनुपात	137
चार्ट IV.38	स्थिर भारत की विदेशी ऋण स्थिति और सुगम संकेतक	138
चार्ट VI.1	ईंधन स्रोतों के संदर्भ में 2022-23 में भारत का प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति मिश्रण और 2024 में स्थापित विद्युत क्षमता	174
चार्ट VI.2	2017 में भारत में कुल 37,000 पेटाजूल (पीजे) ऊर्जा प्रवाह	175
चार्ट VI.3	नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की चौबीसों घंटे (आरटीसी) आपूर्ति	176
चार्ट VI.4	भारत में प्रति व्यक्ति भूमि जी-20ए 2021 में सबसे कम है	181
चार्ट VI.5	महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का भौगोलिक वितरण, 2023	183
चार्ट VI.6	2020 और 2023 में देश द्वारा परिष्कृत सामग्री उत्पादन का हिस्सा	183
चार्ट VI.7	पिछले कुछ वर्षों में मैग्नेट रेयर अर्थ्स का भौगोलिक संकेन्द्रण	184
चार्ट VII.1(क)	भारत में वार्षिक सीएसआर व्यय	202
चार्ट VII.1(ख)	कुल सीएसआर व्यय	202
चार्ट VII.2(क)	बहुआयामी गरीबी का हैडकाउंट अनुपात	204

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट VII.2(ख)	बहुआयामी गरीबी की तीव्रता	204
चार्ट VII.3	बहुआयामी गरीब आबादी में अभावों में कमी	204
चार्ट VII.4	एमपीसीई में सीएजीआर: 2011-12 से 2022-23	206
चार्ट VII.5(क)	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय और जेब से किया गया व्यय	214
चार्ट VII.5(ख)	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय और निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय	215
चार्ट VII.6	उच्च शिक्षा में कुल छात्रों का नामांकन	225
चार्ट VII.7	2014-15 और 2021-22 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में वृद्धि (प्रतिशत)	226
चार्ट VII.8	अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय	230
चार्ट VII.9	नेचर इंडेक्स में शीर्ष दस देशों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्रों में योगदान	231
चार्ट VII.10	सरकार, व्यवसाय उद्यम और उच्च शिक्षा क्षेत्र की भागीदारी, 2020	231
चार्ट VII.11	ग्रामीण गतिविधि का समग्र संकेतक	241
चार्ट VII.12	राज्यों को जारी की गई एमजीएनआरईजीएस निधि का अनुपात और उनकी गरीब आबादी का अनुपात	243
चार्ट VII.13	बेरोजगारी दर (प्रति 1000) और वित्त वर्ष 23 में जारी एमजीएनआरईजीएस फंड	244
चार्ट VII.14	वर्षों से नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदर्शन	245
चार्ट VII.15	एसडीजी में भारत की प्रगति	251
चार्ट VII.16	वर्षों से नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्सपर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदर्शन	252
चार्ट VIII.1(क)	वार्षिक श्रम बाजार संकेतकों में सुधार	256
चार्ट VIII.1 (ख)	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु	257
चार्ट VIII.2	तिमाही शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट	257
चार्ट VIII.3	व्यापक उद्योग प्रभागों द्वारा श्रमिकों का वितरण, 2022-23	258
चार्ट VIII.4	व्यापक श्रेणीवार रोजगार की स्थिति में रुझान	258
चार्ट VIII.5	स्वरोजगार में महिला कार्यबल की हिस्सेदारी	259
चार्ट VIII.6	युवा रोजगार संकेतक	259
चार्ट VIII.7	ग्रामीण भारत महिला एलएफपीआर में वृद्धि	260
चार्ट VIII.8	संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की प्रवृत्ति	261
चार्ट VIII.9	प्रति कारखाना रोजगार में रुझान	261
चार्ट VIII.10	प्रति श्रमिक मजदूरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	261
चार्ट VIII.11	कारखानों और रोजगार की संख्या में शीर्ष छह राज्य	262
चार्ट VIII.12	पांच वर्षों (FY18.FY22) में शीर्ष छह राज्यों में कारखानों में रोजगार में वृद्धि	262
चार्ट VIII.13	छोटे कारखानों की प्रधानता जबकि बड़े कारखाने अधिक रोजगार पैदा करते हैं	263
चार्ट VIII.14	बड़े कारखाने बेहतर मजदूरी का भुगतान करते हैं	263
चार्ट VIII.15	बड़े कारखानों में उच्च रोजगार वृद्धि	264
चार्ट VIII.16	वित्त वर्ष 22 में फैक्ट्री रोजगार में हिस्सेदारी	264
चार्ट VIII.17	5 वर्षों में रोजगार में कुल वृद्धि: वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22	265
चार्ट VIII.18	बढ़ती ईपीएफओ सदस्यता	265
चार्ट VIII.19	म्च्थ्व में निवल पेरोल वृद्धि	266
चार्ट VIII.20	एनसीएस के जरिये जुटाई गई रिक्तियां	266
चार्ट VIII.21	भारत में ओवरटाइम वेज प्रीमियम अधिक है	269
चार्ट VIII.22	राज्यों में महिलाओं के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों की संख्या	270
चार्ट VIII.23(क)	ग्रामीण मजदूरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, पुरुष (वर्तमान मूल्यों पर)	272
चार्ट VIII.23(ख)	ग्रामीण मजदूरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, पुरुष (स्थिर मूल्यों पर)	272

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट VIII.24	गैर-कृषि रोजगार सृजन के लिए वार्षिक आवश्यकता 2024-2036	279
चार्ट VIII.25	पिछले 10 वर्षों में अनुबंधित कर्मचारियों के कार्यबल की बढ़त	280
चार्ट VIII.26	2023 में फ्लेक्सी कार्यबल का क्षेत्रीय वितरण	281
चार्ट VIII.27	बाल देखभाल तक पहुंच की कमी का प्रभाव: एक वैचारिक मॉडल	285
चार्ट VIII.28	औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि	290
चार्ट VIII.29	विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत	290
चार्ट IX.1	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि	300
चार्ट IX.2	प्रमुख खरीफ फसलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता तुलना	301
चार्ट IX.3	प्रमुख फसलों का उत्पादन	302
चार्ट IX.4	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का (जीसीएफ) एवं जीसीफ की कृषि जीवीए में वृद्धि प्रतिशता के रूप में	303
चार्ट IX.5	प्रमुख फसलों के लिए प्रति टन खाद्यान्न जल उपयोग भारत और विश्व औसत	305
चार्ट IX.6	2021-22 से 2023-24 तक प्रमुख फसलों का एमएसपी	309
चार्ट IX.7	अनाज और पोल्ट्री उत्पादों की वृद्धि	315
चार्ट IX.8	प्रमुख राज्यों द्वारा पंजीकृत एकल राज्य और बहु-राज्य सहकारी समितियों की संख्या	317
चार्ट IX.9	विनिर्माण जीवीए में एफपीआई की हिस्सेदारी और प्रतिशत में एफपीआई की वृद्धि	319
चार्ट IX.10	जारी की गई खाद्य सब्सिड	321
चार्ट X.1	कुल जीवीए में उद्योग और उसके घटकों का हिस्सा	324
चार्ट X.2	उद्योगों और उसके घटकों की वार्षिक वृद्धि	324
चार्ट X.3	भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक	324
चार्ट X.4	स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण जीवीए के घटकों में औसत वार्षिक वृद्धि	324
चार्ट X.5	वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 23 के बीच कुल जीवीए में निर्मित उत्पादों के जीवीए के हिस्से में परिवर्तन	325
चार्ट X.6	सीमेंट उद्योग की स्थापित क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग	326
चार्ट X.7	तैयार इस्पात की औसत वार्षिक वृद्धि	327
चार्ट X.8	वित्त वर्ष 24 में तैयार इस्पात की वार्षिक वृद्धि	327
चार्ट X.9	भारत पिछले 5 वर्षों में से 4 वर्षों में तैयार इस्पात का निवल निर्यातक रहा	328
चार्ट X.10	घरेलू खपत के प्रतिशत के रूप में कोयला उत्पादन	329
चार्ट X.11	वित्त वर्ष 24 में फार्मा क्षेत्र का कारोबार, निर्यात और आयात	331
चार्ट X.12	फार्मा क्षेत्र में घरेलू कारोबार वृद्धि	331
चार्ट X.13	कुल कपड़ा (परिधान सहित) जीवीए में गैर-कॉर्पोरेट जीवीए का हिस्सा	333
चार्ट X.14	वस्त्र उत्पादों का कुल निर्यात	333
चार्ट X.15	इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि	335
चार्ट X.16	ऑटोमोटिव पार्ट्स उद्योग का प्रदर्शन	337
चार्ट X.17	विभिन्न श्रेणियों के ऑटोमोबाइल के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि	337
चार्ट X.18	पीएलआई योजना के तहत वास्तविक क्षेत्रवार निवेश	339

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट X.19	सीजीटीएमएसई के तहत स्वीकृत गारंटियों में काफी वृद्धि हुई	340
चार्ट X.20	वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच सीपीएसई के प्रदर्शन में सुधार	343
चार्ट X.21	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या में सुधार हुआ है	343
चार्ट X.22	उद्योग में सकल बैंक ऋण के परिनियोजन में वृद्धि	344
चार्ट X.23	भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास व्यय में उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी: वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21	345
चार्ट XI.1	सेवा क्षेत्र में जीवीए की बढ़ती प्रवृत्ति	350
चार्ट XI.2	सेवा क्षेत्र जीवीए में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में मजबूत गति	350
चार्ट XI.3	कोविड के बाद समग्र जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में मजबूती	351
चार्ट XI.4	सेवा क्षेत्र में व्यापक-आधारित वृद्धि	351
चार्ट XI.5	सक्रिय कंपनियों का आर्थिक गतिविधि-वार विकास	352
चार्ट XI.6	वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच वित्त वर्ष 24 में पीएमआई सेवाओं ने नई उंचाईयों को छुआ	353
चार्ट XI.7	सेवाओं के अंतर्गत चार प्रमुख उप-क्षेत्रों का निर्यात में योगदान	354
चार्ट XI.8	वित्त वर्ष 24 में मजबूत बैंक ऋण निर्माण और वृद्धि	355
चार्ट XI.9	सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में नरमी	356
चार्ट XI.10	रेलवे माल यातायात में निरंतर प्रगति	358
चार्ट XI.11	कोविड के बाद रेलवे यात्री यातायात में सुधार	358
चार्ट XI.12	पोत परिवहन टन भार में निरंतर वृद्धि	359
चार्ट XI.13	हवाई माल यातायात में वृद्धि	360
चार्ट XI.14	हवाई यात्री यातायात में तीव्र वृद्धि	360
चार्ट XI.15	भारत की रैंकिंग में लगातार प्रगति	361
चार्ट XI.16	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) की लचीली बहाली	361
चार्ट XI.17	आतिथ्य सांख्यिकी	362
चार्ट XI.18	व्यक्तिगत गृह ऋण में वृद्धि	364
चार्ट XI.19	कार्यों के अनुसार जीसीसी के उरराजस्व का विभाजन	368
चार्ट XI.20	भारत के टेक स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में डीपटेक का उपयोग मुख्यधारा में आ रहा है	370
चार्ट XII.1	केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय और सीपीएसई और राज्य सरकारों के लिए इसकी सहायता में काफी विस्तार हुआ है	381
चार्ट XII.2	राज्य सरकारों के संयुक्त पूंजीगत व्यय में भी जोरदार विस्तार होता है	381
चार्ट XII.3	इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बकाया क्रेडिट: मार्च 2024	382
चार्ट XII.4	मार्च 2020 से मार्च 2024 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर	382
चार्ट XII.5	मार्च 2020 से मार्च 2024 तक बकाया ऋण में परिवर्तन में हिस्सा	382
चार्ट XII.6	अवसंरचना क्षेत्रों में विदेशी वाणिज्यिक उधार का अंतर्वाह	382
चार्ट XII.7	घरेलू पूंजी बाजार ऋण स्रोतों के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्रों का वित्तपोषण	383
चार्ट XII.8	इक्विटी जारी करने के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्रों का वित्तपोषण	383
चार्ट XII.9	वित्त वर्ष 24 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में एफडीआई इक्विटी इनफ्लो	383

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट XII.10	सड़क परिवहन में निवेश के लिए कुल पूंजी परिव्यय	385
चार्ट XII.11	छभ् नेटवर्क - लेन ऑग्मेंटेशन	385
चार्ट XII.12	रेलवे पर पूंजीगत व्यय	388
चार्ट XII.13	कोच, लोकोमोटिव और वैगनों का वर्षवार उत्पादन	389
चार्ट XII.14	वंदे भारत ट्रेनें और कोचों का उत्पादन	389
चार्ट XII.15	रेलवे विद्युतीकरण की गति	390
चार्ट XII.16	चालू ट्रैक लंबाई	390
चार्ट XII.17	बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्गों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय	391
चार्ट XII.18	प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता	391
चार्ट XII.19	सागरमाला के तहत प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर परियोजना लागत का हिस्सा	392
चार्ट XII.20	सागरमाला के तहत प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित परियोजनाओं का हिस्सा	392
चार्ट XII.21	तटीय शिपिंग और आई डब्ल्यू टी	394
चार्ट XII.22	नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश	398
चार्ट XII.23	ऊर्जा भंडारण क्षमता आवश्यकता	400
चार्ट XII.24	बिजली की स्थापित क्षमता में विभिन्न स्रोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी	401
चार्ट XII.25	बिजली उत्पादन में प्रतिशत हिस्सेदारी	401
चार्ट XII.26	अमृत 1.0 और 2.0 के लिए कुल परिव्यय	407
चार्ट XII.27	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरी की गई परियोजनाओं का मूल्य	408
चार्ट XII.28	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	408
चार्ट XIII.1	विभिन्न खाद्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन	424
चार्ट XIII.2	प्रणाली परिवर्तन की ऊर्जा तीव्रता	425
चार्ट XIII.3	भंडारण लागत से नवीकरणीय ऊर्जा जीवनचक्र लागत बढ़ती है	426
चार्ट XIII.4	डेटा केंद्रों की ओर से बिजली की मांग और अन्य बड़े लोड	428
चार्ट XIII.5	प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपने कुल और प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन के साथ	430
चार्ट XIII.6	निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्थाएं और उनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन	430
चार्ट XIII.7	विभिन्न विचारों के प्रति प्रतिबद्धता वाली अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएँ	433
चार्ट XIII.8	'खाद्य, चारा और खाद्य प्रसंस्करण' के लिए उपयोग की जाने वाली फसल का औसत अंश (1964-1968)	435
चार्ट XIII.9	'खाद्य, चारा और खाद्य प्रसंस्करण' के लिए उपयोग की जाने वाली फसल का औसत अंश (2009-2013)	435
चार्ट XIII.10	लाईफ थीम्स	440
चार्ट XIII.11	प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2025	443

बाक्स की सूची

बाक्स सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
बॉक्स I.1	जीडीपी, जीवीए और उनके घटकों में वृद्धि सुनिश्चित करती है कि मांग और उत्पादन में कोई स्थायी नुकसान नहीं होता है	13
बॉक्स I.2	सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना	27
बॉक्स II.1	औपचारिकीकरण के माध्यम से एमएसएमई को बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ाना	40
बॉक्स II.2	ठप्प पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और घर खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करने में आईबीसी की भूमिका	48
बॉक्स II.3	प्रौद्योगिकी और भारतीय पूंजी बाजार का तालमेल: विकास और दक्षता को बढ़ावा देना	59
बॉक्स II.4	भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज: प्रगति कर रहे हैं	63
बॉक्स III.1	उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति के लिए अत्यधिक जोखिम	81
बॉक्स III.2	वित्त वर्ष 24 में खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक उपाय	85
बॉक्स IV.1	निर्यात बढ़ाने की उत्पाद विशिष्ट सफलता की कहानियाँ	100
बॉक्स IV.2	भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों का सफर	107
बॉक्स IV.3	भारत की जीवीसी भागीदारी और क्षेत्रीय संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति	110
बॉक्स IV.4	निर्यात हब के रूप में भारतीय जनपद	114
बॉक्स IV.5	प्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक	123
बॉक्स IV.6	चीन प्लस वन रणनीति	130
बॉक्स IV.7	विनिमय दर के व्यापार और वित्तीय चैनल	135
बॉक्स V.1	चीनी विनिर्माण प्रभावशाली शक्ति: ईएमई के लिए खतरा	148
बॉक्स V.2	भारत की बढ़ती मोटापे की चुनौती: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य से अवलोकन सर्वेक्षण	150
बॉक्स V.3	किसान-हितैषी नीतिगत ढांचा	153
बॉक्स V.4	बाजार वित्त का लाभ उठाना: भारत द्वारा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का उत्प्रेरक उपयोग	157
बॉक्स V.5	भारत में राज्य क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी का समग्र दृष्टिकोण	160
बॉक्स VI.1	सूक्ष्म सिंचाई पर केस स्टडी- समुदाय-नेतृत्व वाली जल प्रशासन की भूमिका	172
बॉक्स VI.2	ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए उठाए गए कदम	176
बॉक्स VI.3	नवीकरणीय ऊर्जा की चौबीसों घंटे आपूर्ति	179
बॉक्स VI.4	महत्वपूर्ण और दुर्लभ मृदा खनिजों का भौगोलिक संकेन्द्रण	182
बॉक्स VI.5	भारत के लिए संभावित नेट-जीरो की ओर ऊर्जा संक्रमण को समन्वित करने पर रिपोर्ट: सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा	184
बॉक्स VI.6	कार्बन बाजारों का विकास	187
बॉक्स VI.7	लाइफ इन एक्शन भारत का अभिनव ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम	188
बॉक्स VII.1	भारत में डेटा गवर्नेंस में बदलाव: डीजीक्यूआई 2ण्0 और उससे आगे	199
बॉक्स VII.2	बारामूला और गुमला की 'आकांक्षा' से 'परिवर्तन' की ओर प्रगति	200
बॉक्स VII.3	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व - लाभ और उद्देश्य के बीच सेतु का निर्माण	202
बॉक्स VII.4	स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम और ऋण बाजार के परिणामों पर प्रभाव	216
बॉक्स VII.5	'पोषण भी पढ़ाई भी' : आंगनवाड़ियों में प्री-स्कूल नेटवर्क की स्थापना	218
बॉक्स VII.6	विद्यांजलि: एक स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम	222
बॉक्स VII.7	भारत की ऑनलाइन शिक्षण संरचना	228
बॉक्स VII.8	महिला सशक्तीकरण के लिए रोजगार की प्रमुखता: कृष्णगिरि की लड़कियां वित्तीय स्वतंत्रता की स्याही से अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं	237
बॉक्स VII.9	क्या मनरेगा व्यय ग्रामीण संकट का सूचक है?	242
बॉक्स VII.10	ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहल	247
बॉक्स VII.11	ग्रामीण शासन में सुधार के लिए डिजिटलीकरण पहल	250

बाक्स सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
बॉक्स VIII.1	रोजगार सृजन और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने की पहल	266
बॉक्स VIII.2	रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम विनियमों का पुनर्संतुलन	269
बॉक्स VIII.3	रिकार्डो की धुरी और तकनीकी विकल्पों की केंद्रीयता	274
बॉक्स VIII.4	भारत में फ्लेक्सी जॉब मार्केट	280
बॉक्स VIII.5	कृषि-प्रसंस्करण में सह्याद्री की सफलता	282
बॉक्स VIII.6	बेहतर देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण	288
बॉक्स VIII.7	कौशल के लिए उद्योग के साथ साझेदारी	293
बॉक्स VIII.8	पीएम विश्वकर्मा योजना: प्रगति हो रही है	295
बॉक्स VIII.9	शिक्षुता ढांचे को पुन: अंशाकित करना	295
बॉक्स IX.1	पीएमएफबीवाई में हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप	306
बॉक्स IX.2	भारत में कृषि जिंसों के लिए भावी बाजार	307
बॉक्स IX.3	जल प्रबंधन में सुधार के लिए नीतिगत हस्तक्षेप-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव	311
बॉक्स IX.4	लचीला, किसान-हितैषी और पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ उर्वरक सब्सिडी: आगे बढने का सुझाया गया तरीका	312
बॉक्स IX.5	डिजिटल कृषि: डिजिटल क्रांति का मार्ग	314
बॉक्स IX.6	पैक्स के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली को संबोधित करने के लिए पहल	317
बॉक्स X.1	इस्पात क्षेत्र की पहल	328
बॉक्स X.2	कोयला क्षेत्र में हालिया पहल, चुनौतियां और अवसर	329
बॉक्स X.3	फार्मा क्षेत्र की हालिया पहल, चुनौतियां और दृष्टिकोण	331
बॉक्स X.4	फार्मा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने और पुनर्कल्पित करने की आवश्यकता	332
बॉक्स X.5	कपड़ा उद्योग में चुनौतियां और सहायक पहल	334
बॉक्स X.6	इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने की पहल	335
बॉक्स X.7	ऑटोमोबाइल और ई-मोबिलिटी के लिए नीतिगत समर्थन	337
बॉक्स X.8	एमएसएमई ऋण योजनाएं	340
बॉक्स X.9	विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए भवन विनियमों की पुनर्कल्पना	341
बॉक्स X.10	ओडीओपी: क्षेत्रीय गौरव और आर्थिक सशक्तिकरण का निर्माण	342
बॉक्स X.11	भारत में स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास	346
बॉक्स XI.1	पंजीकृत कंपनियों की संख्या में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक बना हुआ है	352
बॉक्स XI.2	विश्वास का निर्माण: रेरा किस प्रकार रियल एस्टेट को नया आकार दे रहा है	365
बॉक्स XI.3	ओएनडीसी - डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण	373
बॉक्स XII.1	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने लिए प्रमुख तंत्र	384
बॉक्स XII.2	सड़क संपर्क बढ़ाने वाली प्रमुख पहल	386
बॉक्स XII.3	सड़क विकास के लिए प्रमुख पहल	387
बॉक्स XII.4	रेलवे संवर्धन के लिए पहल	388
बॉक्स XII.5	रेलवे क्षेत्र में प्रमुख पहल	389
बॉक्स XII.6	बंदरगाहों में प्रमुख पहल	392
बॉक्स XII.7	नए खंड - ड्रोन, लीजिंग और एमआरओ	395
बॉक्स XII.8	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना	396
बॉक्स XII.9	विद्युत क्षेत्र में कुछ प्रमुख पहल	397
बॉक्स XII.10	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम, परियोजनाएं और पहल	398
बॉक्स XII.11	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख नीतियाँ	400
बॉक्स XII.12	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियाँ	400
बॉक्स XII.13	खेल क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम, परियोजनाएं और पहल	402

बाक्स सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
बॉक्स XII.14	स्टील (बर्तन) बैंक: तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले का विचार	403
बॉक्स XII.15	सैलम: टिकाऊ ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए मिजोरम का एक आदर्श गांव	403
बॉक्स XII.16	प्रमुख कार्यक्रम जल संसाधन क्षेत्र	404
बॉक्स XII.17	जल प्रबंधन क्षेत्र में प्रमुख पहल	406
बॉक्स XII.18	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन	407
बॉक्स XII.19	स्मार्ट सिटी मिशन	408
बॉक्स XII.20	स्वच्छ भारत मिशन शहरी पर केस स्टडीज	409
बॉक्स XII.21	अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी	410
बॉक्स XII.22	बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग	411
बॉक्स XII.23	भारतनेट परियोजना	412
बॉक्स XII.24	जीआई क्लाउड – 'मेघराज'	414
बॉक्स XII.25	एनएलपी का कार्यान्वयन गति पकड़ रहा है	417
बॉक्स XIII.1	जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों के सापेक्ष भारत की उपलब्धियां	422
बॉक्स XIII.2	डब्ल्युईओ आउटलुक –2023, 2030 तक दुनिया को पटरी पर लाने के लिए एक वैश्विक रणनीति का प्रस्ताव करता है	423
बॉक्स XIII.3	पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय नीतियों के लिए बदलाव करने की इच्छा और भुगतान करने की इच्छा	432